RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 237 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » गुरुवार » 26-03-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 मुझे पाकिस्तान से जोड़ना हिमंत के दिमाग की कोरी कल्पना है : गौरव गोगोई

6 धर्म, जाति और धर्मांतरण : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

7 आसान नहीं था टीवी से बॉलीवुड का सफर : उल्का गुप्ता

फर्स्ट टेक

सोनिया गांधी की हालत स्थिर, चिकित्सकों की निगरानी में

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह चिकित्सकों की निगरानी में हैं। अस्पताल के मुताबिक, उन्हें मंगलवार रात लगभग 10.22 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर गंगाराम अस्पताल के प्रमुख डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और चिकित्सकों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल ने कहा कि चिकित्सक पेट और 'यूरिनरी ट्रैक्ट' में संभावित संक्रमण के बारे में जानने के लिए जांच कर रहे हैं और उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दी गई हैं। सूत्रों ने पहले कहा था कि सोनिया गांधी संभवतः मौसम में बदलाव के कारण अस्वस्थ थीं और उन्हें देखभाल के लिए भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और उनकी हालत गंभीर नहीं है।

पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का सूचीकरण 48 साल बाद शुरू

पुरी/भाषा। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के 'रत्न भंडार' की बहुप्रतीक्षित सूचीकरण की प्रक्रिया 48 वर्षों के अंतराल के बाद बुधवार को शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के अनुसार, अधिकृत कर्मियों ने पारंपरिक धोती और गमछा पहनकर सुबह करीब 11:30 बजे मंदिर में प्रवेश किया। अधिकारियों ने बताया कि समान की गिनती की प्रक्रिया निर्धारित शुभ मुहूर्त, अपराह्न 12:09 बजे से 1:45 बजे के बीच शुरू हुई। इस दौरान केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से 12वीं सदी के इस मंदिर की दैनिक पूजा-पद्धति प्रभावित नहीं होगी।

रूस का कहना है कि उसने 400 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए

मॉस्को/एपी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 389 ड्रोन मार गिराए। यह हमला रात के दौरान रूस के अलग-अलग इलाकों व क्रीमिया पर किया गया। बताया जा रहा है कि यह हमला चार साल पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। ड्रोन को रूस के 13 क्षेत्रों के साथ-साथ क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर भी रोका गया, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था।

26-03-2026 सूर्यास्त	27-03-2026 सूर्योदय
6:20 बजे	6:08 बजे

BSE	NSE
75,273.45	23,306.45
(+1,205.00)	(+394.05)

सोना	चांदी
15,192 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	246,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दूध के जले

मिल रहा कौन किससे क्योंकर,
मिडिया में जारी है कयास।
पढ़ सुन कर उकताई जनता,
दल कात रहे काता कपास।
सत्ता की चाहत में आए,
दुश्मन भी अब तो पास-पास।
पी रहे छाछ भी फूंक-फूंक,
यूजीसी में कर-कर तपास।।

रोडशो

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी तथा भाजपा नेता एवं पूर्व तेलंगाना राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन बुधवार को चेन्नई जिले के मायलापुर विधानसभा क्षेत्र में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित रोडशो के दौरान।

सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा

मोदी ने युद्ध जल्द खत्म करने पर जोर दिया, हम पाकिस्तान की तरह 'दलाल राष्ट्र' नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम एशिया में युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे सभी को नुकसान हो रहा है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष में कथित मध्यस्थता के संदर्भ में पाकिस्तान को ''दलाल'' राष्ट्र करार दिया। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि इस मामले में पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रयासों में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि उस देश का 1981 से अमेरिका द्वारा ''इस्तेमाल'' किया जा रहा है।

यह जानकारी मिली है कि जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए संसद परिसर में बुलाई गई बैठक में उपस्थित नेताओं से कहा, ''हम दलाल राष्ट्र नहीं हैं।'' सूत्रों के अनुसार, सरकार ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि भारत सरकार इस मामले पर चुप है और कहा कि ''हम टिप्पणी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं।'' सरकार का पक्ष था कि जब ईरान दूतावास खोला गया, तो विदेश सचिव ने तुरंत वहां दौरा किया और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।

धुरंधर फिल्म विवाद: माधवन ने स्पष्टीकरण दिया

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेता आर. माधवन ने फिल्म धुरंधर: द रिवेंज के एक दृश्य को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें उनके किरदार को सिख धार्मिक ग्रंथ 'दसम ग्रंथ' का कथित तौर पर छंद पढ़ते और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब शिवसेना (शिंदे गुट) से संबद्ध 'सिख्स इन महाराष्ट्र' संगठन के अध्यक्ष गुरजोत सिंह कीर ने फिल्म निर्देशक आदित्य धर, मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह और माधवन सहित फिल्म की टीम पर गुरबानी का अपमान करने और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

माधवन ने मंगलवार शाम को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश पोस्ट करके स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, धुरंधर परिवार की ओर से, हम आप सभी को इतना प्यार देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हाल ही में हमें पता चला है कि कुछ लोगों को इस बात से ठेस पहुंची है कि फिल्म के एक दृश्य में, गुरु गोविंद सिंह के दसम ग्रंथ की पंक्तियाँ पढ़ते समय, मैंने सिगरेट पी थी, और इससे उन्हें दुख हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह बिल्कुल गलत है।

अभिनेता ने कहा कि यह एक गलतफहमी है और स्पष्ट किया कि उन्होंने पंक्तियाँ पढ़ने से पहले सिगरेट खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इस सीन से पहले, इस डायलॉग को बोलने से पहले, आदित्य धर, जो मुझसे भी अधिक इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, ने मुझे सिगरेट को अच्छी तरह बुझा देने के लिए कहा था।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए मैंने सिगरेट को ठीक से बुझा दिया था।

महादेव ऐप:

ईडी ने 1,700 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन जांच के तहत ''अवैध'' महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मुख्य प्रवर्तकों में से एक, सौरभ चंद्राकर से जुड़े संगठनों की दुबई में स्थित लगभग 1,700 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने पहले बताया था कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाह शामिल हैं। सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी कर दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में कुछ संपत्तियों सहित कई विला और महंगे घरों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

ईरान ने अमेरिका का युद्धविराम प्रस्ताव खारिज किया

इजराइल व खाड़ी अरब देशों पर जमीनी हमले तेज किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई/एपी। ईरान ने बुधवार को पश्चिम एशिया में युद्धविराम के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इजराइल व खाड़ी अरब देशों पर हमले तेज कर दिए।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से जुड़े विभिन्न गुटों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लड़ाई 'उन सीमाओं को पार कर चुकी है, जिनकी कल्पना नेताओं ने भी नहीं की थी'।

युद्धविराम प्रस्ताव के बावजूद ईरान ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गयी।

ईरान ने ये जवाबी हमले ऐसे समय में किये हैं, जब इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और वाशिंगटन ने क्षेत्र में पैराट्रूपर्स व अधिक संख्या में मरीन सैनिकों की तैनाती की। ईरान के सरकारी समाचार प्रसारक 'प्रेस टीवी' ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए देश को एकजुट होना होगा : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को यहां मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के संकट से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे देश को एक साथ आना होगा।

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के कारण जहाजों की आवाजाही रुक गई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं।

गोयल ने कहा, ''वहां युद्ध हो रहा है, जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। भारत किसी भी तरह से इस युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन जब युद्ध होता है, तो उसका नुकसान दूसरों को भी झेलना पड़ता है और मुश्किलें आती हैं। मुमकिन है कि मालाबार समूह को पश्चिम एशिया के देशों में सामान भेजने में दिक्कत आ रही हो। लेकिन यह ऐसा समय है जब पूरे देश को एकजुट होना होगा। समय की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को साथ आना पड़ेगा।''

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने 38 विकसित देशों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

इन समझौतों की वजह से भारतीय सामान को दुनिया के दो-तिहाई बाजारों में खास जगह मिल रही है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय उद्योगों, किसानों, छोटे व्यापारियों और कारीगरों को अपनी गुणवत्ता बेहतर करके इन मौकों का फायदा उठाना चाहिए।

हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस बाबत इस गिरोह के 10 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है और अत्याधुनिक विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मॉड्यूल कथित रूप से पुरानी दिल्ली से संचालित हो रहा था और यह सीमा पार नेटवर्क हिस्सा है, जो दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में आपराधिक गिरोहों को अवैध हथियार की आपूर्ति करता था।

मोदी सरकार में मजबूरी नहीं, संकल्प के साथ हो रहा है आर्थिक सुधार : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार से पहले मजबूरी के चलते आर्थिक सुधार किए जाते थे, लेकिन अब ''संकल्प और प्रतिबद्धता'' के साथ यह किया जा रहा है तथा देश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वित्त विधेयक, 2026 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की अकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की।

सीतारमण ने कहा, ''पहले की तरह मजबूरी में सुधार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ सुधार किए जा रहे हैं।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने पर काम किया गया है ताकि ईमानदार करदाताओं को कठिनाई नहीं हो।

सीतारमण ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जीवनयापन की सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) और कारोबार की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) का मजाक बनाया, लेकिन सरकार इन दोनों पहलुओं पर लगातार आगे बढ़ रही है।

सभी हाई स्कूल में दो-तीन वर्ष में ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा : शिक्षा मंत्री प्रधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत के सभी हाई स्कूल में अगले 2-3 वर्ष के भीतर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होगा।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधान ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी प्रकार की शिक्षा को कृत्रिम मेधा (एआई) के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षकों को एआई ज्ञान प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। प्रधान ने कहा कि देश में इस समय लगभग 60 प्रतिशत हाई स्कूल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, अगले 2-3 साल में देश के सभी हाई स्कूल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ जाएंगे। एआई पर मंत्री ने कहा कि देश इस तकनीक में सबसे आगे है।

प्रधान ने कहा, एआई एक ऐसा विषय है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त है। आज, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए पाठ्यक्रम को लागू कर रहे हैं..., एआई का प्राथमिक ज्ञान कक्षा तीन से होगा। उन्होंने कहा कि लगभग सभी मातृभाषाएं एआई से जुड़ी हुई हैं। मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकतर स्कूल राज्यों और केंद्रशासित

प्रदेशों की सरकारों के दायरे में आते हैं। प्रधान ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के महत्व और स्कूली पाठ्यक्रम में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है। आवश्यक विषयों, कौशल और क्षमता आदि के पाठ्यचर्या एकीकरण के तहत, नीति में उल्लेख किया गया है कि सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशल को विकसित करने के लिए प्रासंगिक चरणों में एआई, डिजाइन 'थिंकिंग' आदि जैसे समसामयिक विषयों की शुरुआत सहित ठोस पाठ्यचर्या और शैक्षणिक पहल की जाएगी। प्रधान ने कहा, इस पहल का उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

मंत्री ने बताया कि ग्यारहवीं कक्षा के कंप्यूटर विज्ञान और ग्यारहवीं कक्षा की सूचना विज्ञान प्रथाओं की मौजूदा एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करती हैं। स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) के बीच जागरूकता और मूलभूत दक्षताओं और शिक्षकों के बीच एआई साक्षरता के निर्माण के लिए एआई को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में स्कूली शिक्षा में कृत्रिम एआई और 'कम्प्यूटेशनल थिंकिंग' (सीटी) को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। प्रधान ने कहा, इस पहल का उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली छात्रों में एआई-तत्परता विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में कक्षा 3 से 8वीं

हैदराबाद में फर्जी दंत चिकित्सक गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के हैदराबाद में पिछले 14 वर्षों से कथित तौर पर एक अवैध क्लिनिक संचालित करने और खुद को दंत चिकित्सक बताने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पता चला कि आरोपी के पास बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) की डिग्री नहीं थी और वह बिना अनुमति के 14 वर्षों से दंत चिकित्सालय का संचालन कर रहा था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि ओल्ड नेरेडमेट स्थित क्लीनिक के संबंधित विभाग से अनुमति लिए बिना संचालित होने की विश्वसनीय सूचना के आधार पर 24 मार्च को वहां निरीक्षण किया गया था। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में नेरेडमेट थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

राज्यसभा में शुक्रवार को वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसद द्वारा 2026-27 के बजट कार्य को पूरा करने के लिए शुक्रवार को राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा किए जाने की संभावना है।

संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने उच्च सदन में कहा कि शुक्रवार को उच्च सदन में वित्त विधेयक को विचार के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने राज्यसभा सदस्यों को अगले तीन से चार दिनों की प्रस्तावित कार्यसूची की जानकारी दी। वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस सदस्य जयराम रमेश ने रीजीजू से अनुरोध किया कि वह सदन को आगामी तीन से चार दिनों के लिए सरकार के एजेंडे के बारे में सूचित करें। रीजीजू ने कहा कि 26 मार्च को संसद में अवकाश होने के कारण कामकाज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में शुक्रवार को गैर-सरकारी कामकाज होता है लेकिन 27 मार्च, 2026 को वित्त विधेयक को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले शनिवार और रविवार को भी संसद सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब इन दोनों दिन सामान्य साप्ताहिक अवकाश रखने का निर्णय लिया है। संसद में 30 मार्च से प्रस्तावित कामकाज होगा।

केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने को कहा

हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 2027 में चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 'अग्निवीरों' के पुनर्वास के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने को कहा है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मदन शील शर्मा ने कहा कि यह पत्र मुख्यमंत्रियों को संबोधित है। पत्र प्राप्त होने के बाद, हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक रिपोर्ट भेजी है। मंत्रालय ने वन रक्षक, खनन रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, दमकलकर्मी, घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) जैसे पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा है।

तेलंगाना: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीवन रेड्डी ने छोड़ी पार्टी

करीमनगर/भाषा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी. जीवन रेड्डी ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रेड्डी ने जगतियाल जिला मुख्यालय में समर्थकों के साथ हुई बैठक में अपने इस्तीफे की घोषणा की। रेड्डी के इस फैसले के साथ ही पार्टी से उनका लंबे समय से जुड़ा नाता टूट गया। रेड्डी ने कांग्रेस और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को संबोधित किया और इसकी प्रतियां पार्टी के राज्य नेतृत्व को भी भेजीं।

जगतियाल जिले के वरिष्ठ नेता रेड्डी लगभग चार दशकों से कांग्रेस से जुड़े रहे थे।

रेड्डी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बावजूद मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली और पिछले 20 महीनों से मैं मानसिक तनाव से जूझ रहा हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर मान्यता न मिलने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है और ऐसे माहौल में बने रहने से बेहतर है कि वह पद छोड़ दें, जहां उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन रेड्डी अपने रुख पर अडिग रहे।

बस्तर पर से 'लाल आतंक' का साया हटा, सुविधा केंद्रों में बदले जाएंगे सुरक्षा शिविर : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जगदलपुर (छत्तीसगढ़)/भाषा। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को कहा कि बस्तर क्षेत्र और राज्य का अन्य हिस्सा काफी हद तक 'लाल आतंक' के चंगुल से बाहर निकल आया है और अब लगभग 400 सुरक्षा शिविरों को सुविधा केंद्रों में बदलने की योजना पर काम जारी है।

बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में स्थित पुलिस समन्वय केंद्र 'शौर्य भवन' में आत्मसमर्पण और पुनर्वास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि इन शिविरों को धीरे-धीरे थानों, स्कूलों, अस्पतालों और लघु वनोपज के संग्रह तथा प्रसंस्करण केंद्रों में बदल दिया जाएगा। इस अवसर पर शीर्ष माओवादी कमांडर पापा राव ने 17 अन्य माओवादियों के साथ मिलकर 'पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन' पहल के तहत आत्मसमर्पण कर दिया।

राज्य के गृह मंत्री शर्मा ने कहा, ''आज बस्तर और पूरा छत्तीसगढ़ 'लाल आतंक' के चंगुल से बाहर है। बस्तर अब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है।'' उन्होंने गलत सूचनाओं के प्रति आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि बस्तर के प्राकृतिक संसाधन 'जल, जंगल, जमीन' स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से युवाओं के हैं, और उन्हें इनकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास लघु वनोपज के माध्यम से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है।

करोल बाग में बस पलटी, दो लोगों की मौत, 23 व्यक्ति घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जयपुर से आ रही एक तेज रफ्तार 'स्लीपर बस' मंगलवार देर रात यहां करोल बाग के झंडेवालान इलाके में हनुमान मंदिर के पास एक मोड़ पर मुड़ने के दौरान पलट गई जिससे दो यात्रियों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रात करीब एक बजे करोल बाग थाने को घटना की सूचना मिली जिसमें बताया गया कि दुर्घटना के बाद कई यात्री एक बस के अंदर फंसे हुए हैं। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रोहित राजबीर ने एक बयान में बताया कि जयपुर से दिल्ली आ रही बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। दुर्घटनास्थल के पास एक चौकी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस तेज गति से चल रही थी और मंदिर के पास एक गोलचक्कर पर मोड़ लेते समय नियंत्रण खो देने के बाद पलट गई। अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम यातायात व्यवस्था संभाल रही थी, तभी उन्हें गोलचक्कर के पास एक तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, हम तुरंत मौके पर पहुंचे, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कई लोग गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश में शीशे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। गाड़ी मोरी गेट की ओर जा रही थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा को भी इस घटना के संबंध में देर रात 1.10 बजे सूचना मिली। प्रत्यक्षदर्शी गोकुल ने कहा, भगवान का शुक्र है, यातायात का मार्ग बदलने के लिए हाल में वहां पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। पुलिस की मौजूदगी के कारण एक बड़ी घटना टल गई। अधिकारी ने बताया कि करोल बाग थाना प्रभारी (एसएचओ) के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम, दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मियों, पिकेट स्टाफ और रात्रि गश्त कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत प्रयास शुरू किए गए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन किसानों के खातों में 495 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की

रायपुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के 4.95 लाख से अधिक भूमिहीन कृषकों के खातों में 495 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि साय ने आज बलौदा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि अंतरित की। साय ने अपने संबोधन में कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को सरकार तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा कर रही है।''

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से गृह प्रवेश कराते हुए मकानों की चाबियां भी सौंपीं। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना पैदा हुई है।

संशोधित 'उड़ान' योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 28,840 करोड़ रुपए का प्रावधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दे दी। अगले 10 साल के लिए 28,840 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना के तहत हवाई अड्डों के विकास, उनके रखरखाव और भारत में निर्मित विमानों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

एयरलाइन कंपनियों को इन मार्गों पर उड़ानों के परिचालन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने (वीजीएफ) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाली 10 साल की अवधि में 10,043 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संशोधित योजना के तहत राज्यों के सहयोग से मौजूदा 100 हवाई पट्टियों को हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए आठ वर्षों में 12,159 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना का लक्ष्य आठ वर्षों में 3,661 करोड़ रुपए की लागत से 200 आधुनिक हेलीपैड बनाना है। इनका विकास मुख्य रूप से पिछड़े जिलों में अंतिम छोर तक पहुंच और आपातकालीन सेवाओं के लिए होगा। विमानों और हेलीपोर्ट के रखरखाव के लिए तीन साल तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत प्रति हवाई अड्डा अधिकतम 3.06 करोड़ रुपए सालाना और प्रति हेलीपोर्ट या जल विमान केंद्र के लिए 90 लाख रुपए सालाना की मदद मिलेगी। करीब 441 ऐसे केंद्रों के लिए कुल 2,577 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में छोटे विमानों और हेलिकॉप्टर की कमी को दूर करने तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) से पवन हंस के लिए दो 'ध्रुव' हेलिकॉप्टर और अलायंस एयर के लिए दो 'डोर्नियर' विमान खरीदने का भी प्रस्ताव है।

कच्चे तेल के दाम में नरमी से बाजार में दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़ा, निफ्टी भी मजबूत

मुंबई/भाषा। स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 394 अंक के लाभ में रहा। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच कच्चे तेल के दाम में कमी और वैश्विक बाजारों में मजबूती के साथ घरेलू शेयर बाजार बढ़त में रहे। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,205 अंक यानी 1.63 प्रतिशत बढ़कर 75,273.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,781.31 अंक चढ़कर 75,849.76 अंक पर पहुंच गया था। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 394.05 अंक यानी 1.72 प्रतिशत बढ़कर 23,306.45 अंक पर बंद हुआ।

वर्ष 2030 तक 700 अरब डॉलर का होगा भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र: रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र वर्ष 2030 तक 700 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए पैसा जुटाने की व्यवस्था अब भी बेहद बिखरी हुई और कमजोर है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश में इलाज के कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा आज भी लोगों को अपनी जेब से ही भरना पड़ता है।

'प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस' और 'नैटहेल्थ' की संयुक्त रिपोर्ट 'इंडिया हेल्थ फाइनेंसिंग पोजिशन पेपर 2026' यानी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा जुटाने की मौजूदा स्थिति पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय स्वास्थ्य सेवा का मूल्य लगभग 300 अरब डॉलर था, जिसके 2030 तक 700 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर की बीमारियों का 20 प्रतिशत बोझ यानी हर पांचवां मरीज भारत में है, लेकिन वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में भारत की हिस्सेदारी महज एक प्रतिशत है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2035 तक 200 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। निवेश किए गए हर 10 लाख डॉलर से 23-27 नए रोजगार पैदा होते हैं।

रिपोर्ट बताती है कि भारत में इलाज के कुल खर्च का 44 प्रतिशत हिस्सा 'आउट-ऑफ-पॉकेट' यानी अपनी जेब से दिया जाता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। लगभग 43 करोड़ भारतीय किसी भी प्रभावी बीमा कवर से बाहर हैं।

इसके मुताबिक, भारत में प्रति 1,000 लोगों पर केवल 0.9 चिकित्सक और 1.6 बिस्तर उपलब्ध हैं। 2035 तक देश को 10 लाख चिकित्सकों और 14.5 लाख अतिरिक्त बिस्तर की जरूरत होगी।

नैटहेल्थ की अध्यक्ष और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लि. की प्रवर्तक एवं कार्यकारी चेयरपर्सन अमीरा शाह ने कहा, बिना स्वस्थ भारत के 'विकसित भारत' का सपना पूरा नहीं हो सकता और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत बदलने के लिए निजी व सरकारी क्षेत्र की भागीदारी यानी मिलकर काम करने पर जोर दिया।

केंद्र ने केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की

नई दिल्ली/भाषा। लद्दाख की पैंगोंग झील में 'फ्रोजन मैराथन' से लेकर लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग और 'स्नॉर्कलिंग' जैसी जलीय खेल गतिविधियों तक, सरकार ने केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए विविध विशेष पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार सक्रिय रूप से, विभिन्न नए पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, जिनमें खगोल पर्यटन, 'इको-टूरिज्म', प्रकृति या जैव विविधता पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन, 'वेलनेस' पर्यटन, 'एडवेंचर', 'क्रूज' और ग्रामीण पर्यटन शामिल हैं। सांसद दर्शना सिंह ने जानना चाहा था कि क्या केंद्र सरकार ने केंद्रशासित प्रदेशों में नए प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और विशेष रूप से द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों में 'इको-टूरिज्म' को बढ़ावा देने के प्रयास हुए हैं या नहीं। राय ने कहा कि इन पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों के अनूठे पर्यटन आकर्षण को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है।

विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र बल संबंधी विधेयक पेश किया

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बुधवार को सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश किया और सदन ने इस संबंध में विपक्ष के नोटिस को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। यह विधेयक पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अलग-अलग सेवा नियम व्यवस्था के मौजूदा तंत्र की जगह, विभिन्न सीएपीएफ बलों में कर्मियों को नियंत्रित करने वाला एक एकीकृत कानूनी ढांचा बनाने का प्रावधान करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए इससे संबंधित चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सीएपीएफ धारा 312 के तहत शासन प्रणाली को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करता है, उन्होंने कहा कि बलों के कर्तव्य, शक्तियां और शासन उनके मौजूदा जनादेश के तहत बरकरार रहेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संसद के विधायी अधिकार का जोरदार बचाव किया और कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार संविधान ने दिया।

संसद ने दी उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक को मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसद ने बुधवार को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया तथा सरकार ने आश्वासन दिया कि इस समुदाय के लोगों की गरिमा को बरकरार रखा जाएगा और उनके खिलाफ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।

उच्च सदन में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सभी सदस्यों ने उभयलिंगी समुदाय के लोगों के कल्याण को लेकर समान रूप से चिंता जतायी। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि उनकी न्याय की पुकार है। नरेन्द्र मोदी सरकार समाज के सभी लोगों के उत्थान और उन्हें आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रस्तावित कानून उभयलिंगी लोगों को सशक्त बनाने वाला है और उस समुदाय को उसका

गौरव लौटाएगा, जिसे सदियों से वंचित रखा गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि 2019 में उभयलिंगी व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए एक कानून लाया गया था और अब यह संशोधन विधेयक जटिल प्रावधानों में बदलाव कर उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए लाया गया है, जिनकी अपनी लैंगिक पहचान निर्धारित करने में खुद की कोई गलती नहीं होती। उन्होंने कहा, ''हम चाहते हैं कि इस समुदाय के लोग भी समानता के साथ जिएं। उन्हें भी अन्य लोगों की तरह अधिकार मिलें।'' उन्होंने कहा कि यह कदम सभी वर्गों को एक समान बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

मंत्री ने कहा, ''इस कानून का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा, जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है। उचित कानून के अभाव में उन्हें (उभयलिंगी) गंभीर सामाजिक बहिष्कारों का सामना करना पड़ता है।'' यह विधेयक समुदाय के एक विशिष्ट वर्ग में ऐसी असुरक्षा का समाधान करने के लिए लाया गया है, जो जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं और जिनमें उनकी कोई गलती नहीं होती।

द्रमुक महिला विरोधी, तृणमूल कांग्रेस गरीबों पर अन्याय करने वाली : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चेन्नई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को लोकसभा में इन दोनों प्रदेशों की सरकारों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि द्रमुक सरकार महिला विरोधी है, वहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है।

उन्होंने सदन में वित्त विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान का उल्लेख किया और कहा कि द्रमुक सरकार महिलाओं के खिलाफ है और इस बार महिलाओं का समर्थन उसे नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया जा रहा है। सीतारमण ने आरोप लगाया, ''तमिलनाडु की द्रमुक सरकार महिलाओं के खिलाफ है। उसे महिलाओं का समर्थन नहीं मिलेगा।'' जब कुछ विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई तो वित्त मंत्री ने कहा कि यह शर्मनाक है कि विपक्षी दलों के लोग द्रमुक के समर्थन में खड़े हैं। द्रमुक सदस्यों के सदन में मौजूद नहीं रहने को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, जब भी मैं बोलती हूं तो द्रमुक के सदस्य सदन में नहीं बैठते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस भी ऐसा ही करती है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र से जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया ताकि परिसीमन, सीट वृद्धि और राज्यों के प्रतिनिधित्व के वर्तमान हिस्से को तीस वर्षों तक जारी रखने की गारंटी के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किए जा सके। महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने की तैयारी संबंधी खबरों को लेकर स्टालिन ने कहा था, यह कदम संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 के अनुरूप नहीं है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने पारित किया था और न ही यह उनके उस पहले के रुख के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि इस ऐतिहासिक पहल को केवल 2026 के बाद कराई जाने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन होने के बाद ही लागू किया जाएगा। सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना असम में लागू की और सात लाख चाय बागान श्रमिकों को फायदा हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार चाय बागान में काम करने वाले 3.7 लाख श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है।

उन्होंने आयुष्मान भारत और कुछ अन्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन्हें लागू नहीं किया है। सीतारमण ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन ने पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और फिर तृणमूल कांग्रेस ने भी यही किया।

पेरियार से लेकर करुणानिधि, स्टालिन सभी ने महिला अधिकारों का समर्थन किया : द्रमुक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। द्रविड़ मुनेत्र कषगम् (द्रमुक) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि तमिलनाडु के और पार्टी के प्रमुख नेता हमेशा महिला अधिकारों के पक्षधर रहे हैं। द्रमुक सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने सदन में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि तमिलनाडु हमेशा से महिला अधिकारों का पैरोकार रहा है। उनका कहना था, ''चाहे पेरियार रहे हों, करुणानिधि रहे हों या फिर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन, सभी महिला अधिकारों और सशक्तीकरण के पक्षधर रहे हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए।'' इससे पहले, वित्त मंत्री सीतारमण ने सदन में वित्त विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान का उल्लेख किया और कहा कि द्रमुक सरकार महिलाओं के खिलाफ है और इस बार महिलाओं का समर्थन उसे नहीं मिलेगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र से जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया ताकि परिसीमन, सीट वृद्धि और राज्यों के प्रतिनिधित्व के वर्तमान हिस्से को तीस वर्षों तक जारी रखने की गारंटी के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किए जा सके। महिला आरक्षण को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने की तैयारी संबंधी खबरों को लेकर स्टालिन ने कहा था, ''यह कदम संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 के अनुरूप नहीं है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने पारित किया था और न ही यह उनके उस पहले के रुख के अनुरूप है जिसमें कहा गया था कि इस ऐतिहासिक पहल को केवल 2026 के बाद कराई जाने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन होने के बाद ही लागू किया जाएगा।''

अन्नाद्रमुक ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, पलानीस्वामी पुनः एडप्पाडी सीट से चुनाव लड़ेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल 'आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम' (अन्नाद्रमुक) ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची बुधवार को जारी की। अन्नाद्रमुक राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसने अपने प्रमुख और विपक्ष के नेता के. पलानीस्वामी को सेलम जिले में उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र एडप्पाडी से पुन: उम्मीदवार बनाया है और अन्य कई विधायकों एवं पूर्व विधायकों को भी उनके पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्रों से एक बार फिर मैदान में उतारा है।

पूर्व मंत्री और चेन्नई शहर के प्रमुख नेता डी जयकुमार उत्तर चेन्नई के रोयापुरम से चुनाव लड़ेंगे और राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व मंत्री सी वी षणमुगम विल्लुपुरम जिले के मैलम से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अन्नाद्रमुक के शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे सी विजयभास्कर विरालिमलाई से चुनाव लड़ेंगे। अन्नाद्रमुक ने अपनी पहली सूची में विधायकों के पी मुनुसामी और डिंडीगुल में सी श्रीनिवासन को बरकरार रखा और उन्हें उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों क्रमश: वेप्पनहल्ली (कृष्णागिरि) और डिंडीगुल से उम्मीदवार बनाया। वरिष्ठ नेता एवं विधायक नाथम आर. विश्वनाथन डिंडीगुल जिले के नाथम निर्वाचन क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाएंगे। पार्टी ने पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं एस पी वेलुमणि और पी थंगामणि को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्रों क्रमश: थोंडामुथुर और कुमारपालयम से उम्मीदवार बनाया है। विधायक सेलूर के. राजू और के. पी. अंबलगन क्रमश: मदुरै-पश्चिम और पलाकोड से चुनाव लड़ेंगे। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के नेता आर. कामराज और ओ. एस. मनियन को नन्नीलम और वेदारण्यम से उम्मीदवार बनाया गया है।

पूर्व मंत्रियों कदंबूर सी राजू (विधायक) और आर बी उदयकुमार (विपक्ष के उपनेता) को क्रमश: कोविलपट्टी और तिरुमंगलम से उम्मीदवार बनाया गया है। विरुधुनगर जिले के नेता के. टी. राजेंद्र बालाजी शिवकाशी से चुनाव लड़ेंगे। पी बेंजामिन, एग्री एस एस कृष्णमूर्ति (विधायक), वी वी राजन चेल्लप्पा (विधायक), के सी करुप्पन्नन (विधायक), के सी वीरमणि, एम आर विजयभास्कर और टी एस राजेंद्रन भी इस सूची में शामिल हैं। के सी वीरमणि और सी विजयभास्कर सहित पूर्व मंत्रियों पर सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले दर्ज किए हैं।

नाम तमिलर काची (एनटीके) पहले ही सभी 234 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। अन्नाद्रमुक ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए 27 सीट, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के लिए 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) के लिए 11 सीट आवंटित की हैं।

पिता-पुत्र की हिरासत में मौत मामले में अदालती फैसले के बाद द्रमुक ने पलानीस्वामी से माफी की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने बुधवार को अन्नाद्रमुक पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी तूतुकुड़ी जिले में पिता-पुत्र की हिरासत में मौत मामले में नौ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराए जाने के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। द्रमुक ने पार्टी मुखपत्र 'मुरासोली' में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) पर हमला किया और कहा कि तूतुकुड़ी जिले में 2020 में पिता-पुत्र की हिरासत में हुई मौत के संबंध में अदालत के हालिया फैसले ने पलानीस्वामी के क्रूर प्रशासन को उजागर किया है। उस समय पलानीस्वामी के पास ही गृह विभाग था।

द्रमुक ने 'मुरासोली' में जयराज और फेनिक्स पर रात भर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों पर अदालती निष्कर्षों और पलानीस्वामी के प्रारंभिक बयानों के बीच के अंतर को बताया। द्रमुक ने मामले को प्रारंभिक कार्यवाही के लिए पलानीस्वामी को झूठा करार दिया और उन पर अपराधियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

'मुरासोली' में आरोप लगाया गया है, पलानीस्वामी ने क्या बयान जारी किया? उन्होंने जयराज और फेनिक्स की हत्या को छिपाने की कोशिश की। द्रमुक के मुखपत्र ने दावा किया कि पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन के निरंतर दबाव के कारण ही यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया था।

स्टालिन उस समय राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। मदुरै की एक अदालत ने 23 मार्च को तूतुकुड़ी जिले में जयराज और फेनिक्स की हिरासत में हुई मौत के मामले में सभी नौ आरोपी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जी. मुथुकुमारन ने घोषणा की कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित कर दिया है और उन्होंने पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। दोषी पुलिसकर्मियों को सजा 30 मार्च को सुनाई जाएगी।

उभयलिंगी विधेयक लाकर समुदाय के साथ अन्याय किया है सरकार ने : द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को द्रमुक नेता तिरुचि शिवा ने उभयलिंगी लोगों के बारे में सरकार द्वारा लाये गये एक विधेयक को इस समुदाय के साथ अन्याय करार देते हुए इसे वापस लेने या प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया। उच्च सदन में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए शिवा ने कहा कि वह इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर आज सुबह चेन्नई से आये हैं। उन्होंने कहा कि वह बेहद दुख एवं पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि उभयलिंगियों के साथ एक बार फिर अन्याय होने जा रहा है।

उन्होंने सरकार को आगाह किया कि वह भले ही अपने बहुमत के बल पर इस विधेयक को पारित करवा ले किंतु यह उच्चतम न्यायालय में खारिज हो जाएगा क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह उभयलिंगी वर्ग के लोगों का सम्मान से जीवन जीने के अधिकार, निजता आदि के अधिकारों का हनन करता है। शिवा ने कहा कि विधायिका का काम होता है कि वह लोगों के कष्टों एवं समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाये लेकिन इस मामले में ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो लोगों के विरुद्ध हो।

उन्होंने उभयलिंगी वर्ग की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि समाज में पहले ही उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है किंतु अब सरकार इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से उन्हें कई मायने में आपराधिक दायरे में ला रही है। द्रमुक सदस्य ने कहा कि सरकार ने 2014 में उभयलिंगी समुदाय के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसी समय नाल्सा ने उच्चतम न्यायालय में सरकार पर एक मामला दायर किया था तथा इसी समय द्रमुक सदस्य ने उभयलिंगी समूह के बारे में उच्च सदन में एक निजी विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि द्रमुक सरकार के शासनकाल में तमिलनाडु में देश का पहला उभयलिंगी कल्याण बोर्ड बनाया गया था।

शिवा ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समवर्ती सूची का विषय है तथा सरकार को बताना चाहिए कि मौजूदा विधेयक लाने से पहले उसने क्या किसी राज्य के साथ या इस समुदाय के लोगों के साथ विचार विमर्श किया था? उन्होंने कहा कि 1970 के 45 साल बाद राज्यसभा में एक निजी विधेयक पारित हुआ जो उनके द्वारा उभयलिंगी समूह के कल्याण के लिए लाया गया विधेयक था। उन्होंने कहा कि इस बारे में यूपीएससी की एक परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था।

द्रमुक सदस्य ने कहा कि इस विधेयक पर लोकसभा में सात बैठकों में चर्चा हुई तथा सरकार ने उनसे भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार अभी जो विधेयक लेकर आयी है उसमें उनके द्वारा लिये गये विधेयक के प्रावधानों को बहुत हल्का कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार उच्चतम न्यायालय के इस बारे में दिये गये आदेशों के प्रभावों को हल्का करने के लिए यह विधेयक लायी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित 2019 के अधिनियम में उभयलिंगी समुदाय को आत्म निर्धारण सहित जो अधिकार दिये हैं, उन्हें वापस लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इसे वापस लेने या इसे प्रवर समिति के पास भेजने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोगों और नागरिक समाज से बात करके उनके सुझावों के आधार पर वह नये विधेयक को लेकर वापस आये और उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी।

आचार संहिता लागू होते ही शराब की बिक्री पर बढ़ी सख्त पाबंदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद अधिकारियों ने शराब की बिक्री पर कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं।

साथ ही, इनका दुरुपयोग रोकने के लिए अब सभी आउटलेट कड़ी निगरानी में काम कर रहे हैं। ये प्रतिबंध चुनाव आयोग के उन मानदंडों के अनुरूप हैं जिनका उद्देश्य मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब के इस्तेमाल पर अंकुश लगाकर चुनावों के दौरान निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। चुनाव अवधि के दौरान कड़ी निगरानी को बनाए रखना है। अधिकारियों ने बताया कि संशोधित नियमों के तहत, व्यक्तियों को केवल निर्धारित सीमा के भीतर ही शराब खरीदने की अनुमति है, जिसके बाद वैध औचित्य के बिना इसका कब्ज़ा गैरकानूनी माना जाएगा।

निर्धारित सीमा में 4.5 लीटर इंडियन मेड फॉरेन स्पिरिट्स (आईएमएफएस) या आयातित शराब, 7.8 लीटर बीयर और नौ लीटर तक वाइन शामिल हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन टीमों को पूरे राज्य में अनुपालन की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। हमने सभी खुदरा दुकानों को बिना किसी अपवाद के इन सीमाओं को लागू करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, अनुमत मात्राएं केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए हैं और किसी भी उल्लंघन से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। निगरानी को मजबूत करने के लिए, राज्य के 4,787 तस्माक आउटलेट्स पर होने वाले सभी लेनदेन को चेन्नई से संचालित एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य बिलिंग और वास्तविक समय डेटा अपलोड निगरानी प्रयासों का आधार बनेंगे।

इस कार्रवाई से चुनाव अवधि के दौरान, विशेष रूप से निजी कार्यक्रमों और सभाओं के लिए, आमतौर पर देखी जाने वाली थोक खरीदारी की प्रवृत्ति पर काफी हद तक अंकुश लगने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह की खरीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के प्रयासों के तहत निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

515 एबीडब्ल्यू ने ड्रोन निर्माण और इकोसिस्टम की मजबूती के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

बेंगलूरु। भारतीय सेना की 515 आर्मी बेस वर्कशॉप ने रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय / इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय / मुख्यालय बेस वर्कशॉप समूह की ओर से तीन महत्त्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये नई रणनीतिक साझेदारियां प्रमुख संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ पहले के सफल सहयोगों को आगे बढ़ाएंगी। साथ ही, मानवरहित प्रणालियों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण तथा 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। स्वदेशी ड्रोन निर्माण क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए, 515 एबीडब्ल्यू ने स्टार्टअप नॉटिकल विंग्स एयरोस्पेस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह स्टार्टअप उन्नत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, वर्टिकल लिफ्ट समाधान, बीएलडीसी मोटर्स और यूएवी के लिए कंपोजिट संरचनाओं में विशेषज्ञता रखता है। इसके अलावा, 515 एबीडब्ल्यू ने यानेंद्रिय प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह आर्टपार्क, आईआईएससी बेंगलूरु में इनक्यूबेट किया गया एक डीप-टेक स्टार्टअप है। उभरती हुई तकनीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के साथ तीसरा एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। यह साझेदारी ड्रोन फोरेंसिक, साइबर और हार्डवेयर सुरक्षा मूल्यांकन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करेगी। ये एमओयू स्वदेशी क्षमताओं के विकास और नागरिक-सैन्य एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को और मज़बूत करेंगे।

केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए अनुदान न मिलने के कारण राज्य का राजस्व संग्रह कम है : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

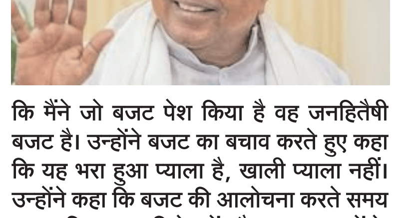

बेंगलूरु। भाजपा सरकार के कार्यकाल (2019-2022) के दौरान केंद्र सरकार ने जीएसटी में राहत प्रदान की। इस अवधि में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई कुल राहत 57,351 करोड़ रुपये थी। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार 2023 से जीएसटी में राहत देना बंद कर देगी। इसके चलते राज्य के राजस्व संग्रह में कमी आई है और उसे राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा है।

बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान, बजट पर हुई बहस के जवाब में विपक्ष के 21 सदस्यों, सत्ताधारी पार्टी जेडीएस के सदस्यों और अन्य सहित कुल 50 लोगों ने अपनी बात रखी। बहस 24 घंटे 45 मिनट तक चली। मैंने 17 बजट पेश किए हैं और यह पहली बार है कि 50 लोगों ने बजट पर अपनी बात रखी और बहस की। उन्होंने अध्यक्ष, डब्ल्यूआईएफएफ के नेताओं और बहस में भाग लेने वाले सभी लोगों को बधाई दी, जिन्होंने बजट की आलोचना, प्रशंसा और समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक राज्य का बजट तभी खाली कहा जा सकता है जब वह भरा हुआ हो। विपक्षी दलों ने बजट पेश करते समय इसकी आलोचना की और कर्नाटक सरकार के बजट को खाली प्याला बताया। उन्होंने कहा कि मैंने जो बजट पेश किया है वह जनहितैषी बजट है। उन्होंने बजट का बचाव करते हुए कहा कि यह भरा हुआ प्याला है, खाली प्याला नहीं। उन्होंने कहा कि बजट की आलोचना करते समय राज्य की जनता, विशेषज्ञों और समाचार पत्रों के संपादकीय लेखों की भावनाओं और विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के संपादकीय और आर्थिक विशेषज्ञों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जैसे कि एक ऐसा बजट जो सभी समुदायों तक पहुंचता है, राज्य के लिए एक टिकाऊ और मजबूत 11जी शैली का बजट, सिंचाई और बुनियादी ढांचे पर जोर, एक लोकप्रिय और यथार्थवादी बजट, एक दूरदर्शी बजट जो राज्य के खजाने को टिकाऊ बनाए रखता है, बेरोजगारी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे पर केंद्रित एक सर्व-समावेशी बजट, निवेश और उद्यमियों की मदद करने वाली परियोजनाओं वाला बजट। इस वर्ष राज्य का बजट 4,48,004 करोड़ रुपये होगा। 2025-26 में हमारा बजट 4,09,549 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में यह बजट 38,455 करोड़ रुपये अधिक है, यानी इसमें 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से, 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अन्याय, केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू न करने और जीएसटी मुआवजे का भुगतान न करने के कारण राज्य को 2,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसे टिक पाएगी? इसके बावजूद हम अपने राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात राज्य, जिसने गारंटी जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, इस बार 1,00,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले रहा है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता की सफलता के लिए समाज के हर व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी स्वतंत्रता सफल होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि हम विरोधाभासों से भरे समाज में प्रवेश कर रहे हैं और असमानता को दूर किए बिना समतावादी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए, हमारी सरकार के लिए जनता को सामाजिक न्याय प्रदान करना और उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। सत्ता में रहते हुए जनता के हित में काम करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है।

सारथी योजना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बुधवार को विधान सौधा के पूर्वी द्वार के सामने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और विभिन्न सामुदायिक विकास निगमों द्वारा आयोजित स्वावलंबी सारथी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वाहन वितरित किए और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पिछड़ा वर्ग कल्याण और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के मंत्री शिवराज एस. थंगदगी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नासिर अहमद और अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्रों से 'डॉक्टर' बनने वालों पर कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान विशेष अभियान समूह(एसओजी) ने कूटरचित 'फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन' (एफएमजीई) प्रमाण पत्रों के जरिए चिकित्सक बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इनमें विदेशों से डिग्री लेकर चिकित्सक बने 15 आरोपी भी शामिल हैं जबकि एक दलाल है। पुलिस के अनुसार अधिकांश मामलों में एक फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के बदले में प्रत्येक अभ्यर्थी से 20 से 25 लाख रुपए लिए जाते थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्रों की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज करके जांच शुरु की गई थी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नयी दिल्ली में स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। अधिकारियों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। अधिकारियों के अनुसार शर्मा ने प्रधानमंत्री को नवरात्र पर्व की शुभकामना और बधाई देते हुए राजस्थान के शिल्पकार द्वारा चंदन की लकड़ी से निर्मित मां दुर्गा की मूर्ति भेंट की। शर्मा ने इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जारी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'डबल इंजन' सरकार की योजनाओं और नीतियों के सफल क्रियान्वयन से आमजन लाभांवित हो रहे हैं और राजस्थान विकास के मामले में नयी ऊंचाइयां छू रहा है।

अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली

जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित जिला और सत्र न्यायालय परिसर में विस्फोटक होने की धमकी से बुधवार को अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा व प्रशासन के अधिकारियों ने परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि, परिसर की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि अदालत परिसर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी डाक से भेजे गए पत्र के जरिए मिली। इसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। जिला पुलिस अधीक्षक हरि शंकर ने कहा, ''हमें अदालत परिसर में बम होने के संबंध में धमकी भरा पत्र मिला था। एहतियाती कदम के तौर पर पूरे परिसर को खाली करा लिया गया और सघन तलाशी ली गई।'' उन्होंने बताया कि बीकानेर से बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। उन्होंने बताया कि टीम ने अदालत कक्ष, चैंबर और न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय सहित पूरे परिसर की तलाशी ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तलाशी अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने पर अदालत परिसर में फिर से काम शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार धमकी भरा पत्र कोलकाता से एक गलत पते का इस्तेमाल करके भेजा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजस्थान में सप्ताहांत आंधी और बारिश का अनुमान

जयपुर। मौसम विभाग ने एक नये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इस सप्ताहांत राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश और आंधी का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य में हालांकि अभी दो तीन दिन मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी दो-तीन दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि 26-27 मार्च को सीमावर्ती क्षेत्रों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28-30 मार्च को राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा जिससे तेज आंधी और बारिश आ सकती है। केंद्र के अनुसार इसी तरह 28 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में आंधी-बारिश हो सकती है। जबकि इस विक्षोभ का सबसे अधिक असर 29-30 मार्च को रहेगा और जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बुधवार सुबह तक पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रमुख शासन सचिव (वित्त) ने हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया ने बुधवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की और परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। निरीक्षण के दौरान गालरिया ने मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने वित्त, आबकारी, ट्रेजरी एवं एकाउंट्स तथा एसआईपीएफ से जुड़े प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 24 मार्च 2026 तक वित्त विभाग से संबंधित कुल 718 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 601 का निस्तारण किया गया।

इन प्रकरणों के निस्तारण में औसतन 26 दिन का समय लगा तथा 68 प्रतिशत परिवादियों ने संतुष्टि व्यक्त की। इसी प्रकार, ट्रेजरी एवं अकाउंट से जुड़े 5118 दर्ज प्रकरणों में से 4775 का निस्तारण किया गया। इनका औसत निस्तारण समय भी 26 दिन रहा तथा 70 प्रतिशत परिवादी संतुष्ट पाए गए। वहीं, एसआईपीएफ से संबंधित 15,198 दर्ज प्रकरणों में से 14,457 का निस्तारण किया गया, जिनमें औसतन 23 दिन का समय लगा और 52 प्रतिशत परिवादियों ने संतुष्टि जताई।

पत्रकारिता के अतीत के साथ हमारी गौरवमय ज्ञान परंपरा से भी विद्यार्थी जुड़ें : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पत्रकारिता के भारतीय अतीत के साथ हमारी गौरवमय ज्ञान-परम्परा से भी जुड़े। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में समाचार के साथ विचार-संस्कृति की शिक्षा का भी प्रसार होना चाहिए। उन्होंने आजादी आंदोलन में पत्रकारिता की रही भूमिका के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, कर्पूर चंद्र कुलिश, बिशन सिंह शेखावत आदि को याद करते हुए पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा के प्रभावी प्रसार का आह्वान किया।

राज्यपाल बागड़े बुधवार को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता का मैं पक्षधर हूं पर पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षा में यह सीख भी दी जाए कि स्वतत्रंता स्वच्छंदता नहीं है। उन्होंने स्वस्थ पत्रकारिता मूल्यों के लिए भावी पत्रकार तैयार किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्यों को सत्य, धर्म और विनम्रता का पालन करने की सीख दी जाती थी। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे प्राप्त ज्ञान का अहंकार न करते हुए समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग करें।

राज्यपाल ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का उल्लेख करते हुए कहा कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ आज भी हमें नैतिकता और जीवन मूल्यों की शिक्षा देते हैं। उन्होंने राजस्थान की पत्रकारिता परंपरा का स्मरण करते हुए कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य सदैव सत्य को सामने लाना और समाज को जागरूक करना रहा है। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि तथा उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि विश्वास अर्जित करने का भी क्षण है। यह जीवन का वह मोड़ है जहां से नई दिशा और जिम्मेदारी शुरू होती है। उन्होंने 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया गया, लेकिन सशक्त पत्रकारिता ने सत्य की रक्षा की। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक मिशन है। आज के दौर में जब डिजिटल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने परिदृश्य को तेजी से बदला है, अब फेक न्यूज की चुनौती भी बढ़ी है। ऐसे में पत्रकारों को सबसे पहले नहीं, बल्कि सबसे सही बनने की होड़ रखनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है।

विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के परिश्रम और संघर्ष को औपचारिक मान्यता मिलने का दिन है। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी एवं पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को स्मरण करते हुए कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण और जनचेतना का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि पहले पत्रकारिता का स्वरूप मुख्यतः प्रिंट मीडिया तक सीमित थाए लेकिन आज डिजिटल माध्यमों ने इसे व्यापक और त्वरित बना दिया है। इसके बावजूद हर वायरल खबर सत्य नहीं होतीए इसलिए पत्रकारिता की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने पेशे के मूल्यों-निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता को बनाए रखें तथा देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 एवं 2025 में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 271 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर के 269 विद्यार्थी तथा 2 शोधार्थी शामिल रहेए जिन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 12 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, जबकि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कुल 35 विद्यार्थियों को वरीयता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

युवक कांग्रेस चुनाव का सीधा असर सीकर की सियासत पर पड़ेगा

बाल मुकुंद जोशी
dakshinbharat.com

गोविंद सिंह डोटासरा

मुकुल खींचड़

मुकुल खींचड़ की यह सक्रियता डोटासरा खेमे को रास नहीं आ रही है, उनके समर्थक अभिषेक चौधरी के पक्ष में मजबूती से रणनीति बिछा रहे हैं।

जयपुर, (दक्षिण भारत न्यूज नेटवर्क)।राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में सीकर जिला हमेशा से शक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि बीते कुछ समय से जिले के वरिष्ठ नेताओं के उम्रदराज होने के चलते संगठनात्मक सक्रियता में कुछ कमी महसूस की जा रही है। ऐसे माहौल में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अकेले दम पर 'हाथ' को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभाल रखी है।

इसी बीच युवक कांग्रेस संगठन के चुनावों ने सीकर की सियासत को फिर से गर्मा दिया है। अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में खड़े महादेव सिंह खण्डेला, राजेंद्र पारीक, दीपेंद्र सिंह शेखावत, परसराम मोरदिया और सुरेश मोदी जैसे दिग्गज 'एक और मौका' मिलने की आस में फिलहाल खामोशी ओढ़े हुए हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए उपजाऊ राजनीतिक जमीन माने जाने वाले सीकर में अब नया नेतृत्व उभरता दिख रहा है। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकुल खींचड़ ने जिस आक्रामक अंदाज में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी है, उसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। उनके तेवर यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में सीकर की राजनीति नए रंग में नजर आ सकती है।

हालांकि मुकुल खींचड़ की यह सक्रियता डोटासरा खेमे को रास नहीं आ रही है, उनके समर्थक अभिषेक चौधरी के पक्ष में मजबूती से रणनीति बिछा रहे हैं। यह मुकाबला केवल संगठनात्मक चुनाव नहीं, बल्कि वर्चस्व और 'चौधराहट' की लड़ाई बनता जा रहा है। डोटासरा खेमे की कोशिश है कि भविष्य में उनके ही क्षेत्र और सामाजिक समीकरण से कोई नई चुनौती खड़ी न हो। इस बीच एक अन्य प्रत्याशी राजकुमार परसवाल का नाम भी चर्चा में है, जिनका संबंध भी सीकर से है, लेकिन मौजूदा माहौल में मुकुल खींचड़ जितनी राजनीतिक ऊर्जा उनके पक्ष में दिखाई नहीं देती।

अगले महीने होने वाले युवक कांग्रेस चुनाव न केवल संगठन की दिशा तय करेंगे, बल्कि सीकर जिले की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत भी दे रहे हैं।राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि इन चुनावों के जरिए सीकर संसदीय सीट की भविष्य की पटकथा भी लिखी जा सकती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य एवं जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार-2026 के लिए मांगे आवेदन

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने वर्ष-2026 के राज्य एवं जिला स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 28 मार्च और जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए 5 अप्रैल, 2026 तिथि निर्धारित की गई है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री आशीष मोदी ने बताया कि भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल 2026) के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति जिला एवं राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार-2026 दिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में 28 मार्च 2026 तक डाक अथवा व्यक्तिश आवेदन जमा करवा सकता है।

श्री मोदी ने बताया कि जिला स्तरीय आवेदन संबंधित जिले के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं, जबकि राज्य स्तरीय आवेदन निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर में जमा कराए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पात्रता एवं अन्य जानकारियों के लिए आवेदक विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं।

पानी और पैसे की कमी नहीं, अधिकारी बेहतर प्रबंधन कर आमजन को पेयजल उपलब्ध कराएं : कन्हैयालाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल प्रबंधन के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जा चुका है। अतः अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से आमजन तक निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री कन्हैयालाल बुधवार को जल भवन में आयोजित पेयजल आपूर्ति एवं समर कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर के मुख्य अभियंताओं, अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में अंतिम छोर तक रहने वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अवैध कनेक्शनों एवं बूस्टरों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव के साथ सतही जल स्रोतों में कमी और भूजल स्तर में गिरावट की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी ग्रीष्मकालीन संवर्धन कार्यों की स्वीकृतियां एवं कार्यादेश शीघ्र जारी किए जाएं। साथ ही सभी स्वीकृत कार्यों को 30 अप्रैल तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी लेकिन किसी कारणवश बंद पड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुनः प्रारंभ किया जाए।

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 से बनेगा बेहतर ईको-सिस्टम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। राज्य सरकार द्वारा 34 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं, जिससे प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर ईको-सिस्टम बन रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण जैसे विभिन्न निर्णयों से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य बदला है। इसी क्रम में सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 लाई गई है, जिससे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास होगा तथा राजस्थान देश-विदेश में विश्वसनीय एवं फ्यूचर रैडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा।

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राइजिंग, रिलायबल एण्ड रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास है। साथ ही, ये नीति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी पूरा करने में मददगार साबित होगी। इस नीति के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, भूमि-जल-ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाएं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।इससे निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास भी सुनिश्चित होगा।

इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को चार विकास मॉडलों पर विकसित किया जाएगा। मॉडल-ए में रीको द्वारा आवंटित भूमि पर पूरी तरह निजी डवलपर द्वारा विकास किया जाएगा। वहीं, मॉडल-बी के अंतर्गत औद्योगिक पार्क के लिए 80 प्रतिशत भूमि विकासकर्ता द्वाराएवं शेष 20 प्रतिशत भूमि रीको द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह, मॉडल-सी के तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी तथा मॉडल-डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी।

औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत हरित विकास को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक प्रदूषण को भी कम किया जाएगा। इसके लिए सीईटीपी पर व्यय का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये प्रति पार्क) का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डवलपर्स को सामान्य अवसंरचना विकास पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।इसकी अधिकतम सीमा 100 एकड़ क्षेत्रफल तक 20 करोड़ रुपये, 100 से 250 एकड़ क्षेत्रफल पर 30 करोड़ तथा 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए 40 करोड़ रुपये होगी।

अवैध मदिरा पर कार्रवाई - वॉश नष्ट, हथकड़ शराब जब्त

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी निरोधक दलों द्वारा गश्त, नाकाबंदी एवं दबिश की कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर वॉश, भट्टियां नष्ट करते हुए अवैध मदिरा को जब्त किया गया। आबकारी आयुक्त नकाते के निर्देशानुसार अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार शर्मा के सुपरविजन में प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

हनुमानगढ़ जिले में आबकारी थाना हनुमानगढ़ एवं संगरिया ने संयुक्त कार्रवाई कार्रवाई करते हुए पन्नीवाली, फतेहपुर, अमरपुरा थेड़ी में 1200 लीटर वॉश नष्ट किया। चुरू में आबकारी निरोधक दल ने 82 पव्वे देशी मदिरा एवं 12 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की। नागौर के परबतसर में पड़त दुकानों के क्षेत्र में दबिश की कार्रवाई कर 500 लीटर वॉश नष्ट करते हुए 10 लीटर हथकड़ शराब बरामद की। मौके पर 2 अभियोग दर्ज किए। चित्तौड़गढ़ जिले में आबकारी थाना क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नाकाबंदी के दौरान ईको वेन से देशी मदिरा सादा के 8 कार्टन, देशी मदिरा लॉयन सादा के 4 कार्टन, बीयर टुबोर्ग स्ट्रॉंग प्रिमियम के 2 कार्टन सहित 14 कार्टन शराब एवं बीयर बरामद कर वाहन चालक पुसलाल प्रजापत के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में आबकारी थाना क्षेत्र बांसवाड़ा व कुशलगढ़ में दबिश की कार्रवाई में 3 हजार लीटर महुवा वॉश नष्ट किया गया। मौके से 48 बोतल अवैध हथकड़ शराब जब्त कर 4 अभियोग दर्ज किए।

बीकानेर हाउस में आयोजित 11 दिवसीय राजस्थान उत्सव का हुआ समापन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com.

जयपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध उत्सवों में एक राजस्थान उत्सव-2026 प्रदेश की अमिट और अनुपम छाप छोड़कर बुधवार को समाप्त हो गया। बीकानेर हाउस परिसर में आयोजित इस 11 दिवसीय राजस्थान उत्सव में जहां एक ओर राजस्थान की कला और संस्कृति का संगम दिखा वहीं दूसरी ओर राजस्थान व्यंजनों के स्वादों ने सब की सराहना समेटी। राज्य की अतिरिक्त आवासीय आयुक्त श्रीमती अंजू ओमप्रकाश ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुभारंभ किया गया राजस्थान उत्सव अपनी पूरी अवधि में राजधानी वासियों के आकर्षण का केन्द्र बना रहा। पूरे उत्सव में महिलाओं, पुरूषों के साथ-साथ हर उम्र के बच्चों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया।

बीकानेर हाउस का प्रांगण मेले की आभा से आलोकित रहा और पूरा परिसर 'राजस्थानमय' नजर आया। 11 दिवसीय इस उत्सव ने न केवल सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया, बल्कि राज्य के कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के लिए आर्थिक अवसर भी सृजित किए। राजस्थान के मशहूर गणगौर उत्सव को देखते हुए बीकानेर हाउस में 200 महिलाओं के समूह ने राजस्थानी परिधानों में गणगौर की सवारी निकाली जिसकों देखने के लिए सैकड़ो की संख्या में दर्शक एकत्रित हुए।

बिहार के मुख्यमंत्री ने बक्सर में 592 करोड़ रुपए की 64 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को समृद्धि यात्रा के दौरान बक्सर जिले में 592 करोड़ रुपए की 64 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने 486 करोड़ रुपए की लागत से 23 योजनाओं का शिलान्यास तथा 106 करोड़ रुपए की लागत से 41 योजनाओं का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। बयान के मुताबिक इस दौरान उन्होंने 7,441 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के तहत 33 करोड़ 17 लाख रुपए का सांकेतिक चेक प्रदान किया, साथ ही 7,859 जीविका स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत 100 करोड़ रुपए का सांकेतिक चेक दिया। बयान में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की विशेष सहायता योजना के तहत अनुदान भुगतान के चेक, आयुष्मान कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तथा कुशल युवा कार्यक्रम के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

दिवाला संहिता से जुड़े नए कानून से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को गति मिलेगी: अनुराग ठाकुर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए लाये गए विधेयक से ''रिफॉर्म एक्सप्रेस'' को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

ठाकुर ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कंपनियों को खत्म करने के बजाय उन्हें बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा, ''इस विधेयक से रिफॉर्म एक्सप्रेस को और गति मिलेगी तथा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।'' भाजपा सांसद ने दावा किया कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान कभी भी बैंकों का संपत्ति गुणवत्ता मूल्यांकन नहीं किया गया और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बही-खाता सही करने का काम किया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2004 से पहले सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 16 प्रतिशत थीं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने घटाकर 7.8 प्रतिशत किया और फिर कांग्रेस (संप्रग) सरकार इसे 12.3 प्रतिशत पर छोड़ गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसे घटाकर 2.3 प्रतिशत पर लाया है। भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता कानून, 2016 लाने के बाद एनपीए की 50 प्रतिशत बरामदगी की और बैंकों का पैसा वापस दिलाया है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक ''रिफॉर्म एक्सप्रेस'' को आगे बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली इंजन है, यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाने वाला और आर्थिक न्याय का इंजन है। उन्होंने परोक्ष रूप से कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ''ये लोग एनपीए की बात करते हैं, जिनके पास जनसांख्यिकी इतिहास का सबसे बड़ा एनपीए है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।''

ठाकुर ने कहा, ''हम 10 साल बाद कानून में संशोधन करने वाले हैं। प्रवर समिति ने पिछले तीन साल में सभी हितधारकों से बात कर रिपोर्ट दी है।'' उन्होंने उल्लेख किया कि विधेयक में यह नया सुधार जोड़ा गया है कि न्यायालय जाने से पहले उसके बाहर ही समाधान कैसे किया जाए।

आज मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, अगली बार वे नागरिकता भी छीन लेंगे : ममता बनर्जी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैनागुड़ी (पश्चिम बंगाल)/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर बुधवार को तीखा हमला करते हुए उनपर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने यह चेतावनी दी कि उनका अगला कदम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के जरिये नागरिकता छीनने का प्रयास हो सकता है।

बनर्जी ने आगामी पश्चिम बंगाल विस चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत राजनीतिक रूप से अहम उत्तर बंगाल से करते हुए यह टिप्पणी की। उत्तर बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा का गढ़ बनकर उभरा है। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के एसआईआर के माध्यम से संवैधानिक संस्थानों का उपयोग ''लोगों के मतदान के अधिकारों को छीनने'' के लिए किया जा रहा है। बनर्जी ने चुनाव से पहले अपनी पहली बड़ी चुनावी रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''निर्वाचन आयोग, भाजपा और केंद्र सरकार संविधान का पालन नहीं कर रहे और मतदान के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमें मध्यरात्रि को आजादी मिली थी और हमें इस पर गर्व है, लेकिन आज वे आजादी को भूल गए हैं। वे संविधान या लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं। वे लोगों के मतदान के अधिकार छीन रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''आज वे मतदान के अधिकार छीन रहे हैं; कल वे एनआरसी लाकर नागरिकता छीन लेंगे।''

कांग्रेस ने 'सन' को बढ़ावा देने की कोशिश में सूर्य की ऊर्जा का दोहन नहीं किया : केंद्रीय मंत्री जोशी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय यह पार्टी 'सन (पुत्र) स्ट्रोक' से जूझ रही थी और इस कारण से उसने 'सन' (सूर्य) की ऊर्जा का उचित दोहन नहीं किया। जोशी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही।

महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है और 10,000 से अधिक किलोमीटर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में लाइन बिछाई गई है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर-दो पर काम चल रहा है तथा इसके बाद कॉरिडोर तीन भी लाया जाएगा। जोशी ने कहा कि दुनिया में पहली बार भारत ने ही 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' की अवधारण दी है। कांग्रेस और पिछली संप्रग सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि ''वे 'सन (पुत्र) स्ट्रोक से जूझ रहे थे और उन्होंने एक 'सन' (पुत्र) को बढ़ावा देने के प्रयास में सूर्य की ऊर्जा का दोहन नहीं किया।'' जोशी के इस बयान पर कांग्रेस के सदस्यों ने आपत्ति जताई। जोशी ने राज्यों में बिजली की कमी संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए यह भी कहा, ''किसी प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। आज देश में 500 गीगावाट से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है जो इनके (कांग्रेस के) समय उत्पादन 250 गीगावाट ही था।''

सरकार उभयलिंगी लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : भाजपा

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बुधवार को भाजपा सदस्यों ने सरकार के उभयलिंगी लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करते हुए विपक्ष पर इस संबंध में घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया और कहा कि वे जब सत्ता में थे तो उन्होंने इस समुदाय के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

उच्च सदन में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के भीम सिंह ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोग भी समाज के अंग हैं और यह सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने समुदाय के हितों के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना चाहते हुए कहा कि वह घड़ियाली आंसू बहा रही है और उसे बताना चाहिए कि वह जब सरकार में थी तो उसने क्या कदम उठाए। इसी सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए और विधेयक का उद्देश्य यह है कि इस समुदाय के खिलाफ कोई अपराध नहीं हो और न ही इस समुदाय के द्वारा अपराध हो। 2021 में घटना हुई थी जिसमें 13 साल के बच्चे का अपहरण कर उसे जबरिया ट्रांसजेंडर बनाया गया था। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकार का मानना है कि न तो समुदाय पर अत्याचार ना हो और ना ही उनके द्वारा अत्याचार हो। उन्होंने महाभारत में अर्जुन द्वारा बृहन्नला का रूप धारण किए जाने का जिक्र करते हुए सरकार को सुझाव दिया कि इस कानून का नाम उसी चरित्र के नाम पर बृहन्नला कानून रखा जाए।

उभयलिंगी समूह संबंधी विधेयक पर व्यापक चर्चा की जरूरत : विपक्ष

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने उभयलिंगी समूह के बारे में सरकार द्वारा लाए गए एक विधेयक में अपील करने के प्रावधान का अभाव बताते हुए इसे वापस लेने या व्यापक चर्चा के लिए प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया।

आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने कहा कि इस विधेयक को लेकर उन लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए जिनके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। उच्च सदन में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2006 पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक में अपील करने के प्रावधान का अभाव है। उन्होंने कहा ''आपने कहा है कि उभयलिंगी के प्रमाणन के लिए 34 हजार लोगों ने आवेदन दिया जिनमें से 32 हजार को सरकार ने प्रमाणन दिया और 5556 के आवेदन खारिज कर दिए गए। ये लोग कहां अपील करेंगे ?'' पाठक ने सवाल किया कि क्या यह बात दूसरे लोग बताएंगे कि अमुक व्यक्ति उभयलिंगी है या नहीं ?

बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि जब पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है तब सरकार को यह विधेयक लाने की क्या पड़ी थी? उन्होंने कहा ''सरकार अगर उभयलिंगी समुदाय के लिए कुछ करना चाहती है तो बेहतर योजनाएं बनाए, न कि इस विधेयक के जरिये उनके अधिकारों को वापस ले।''

सुलता देव ने कहा कि प्रधानमंत्री 'मन की बात' करते हैं लेकिन इस समुदाय को भी तो मन की बात कहने देना चाहिए। उन्होंने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की।

घरों में रखे 10,000 अरब डॉलर के सोने को वित्तीय प्रणाली में लाना चाहिए: पूर्व मंत्री पी.पी. चौधरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत को घरों में रखे सोने के भंडार को वित्तीय प्रणाली में लाया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.पी. चौधरी और बाजार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यह बात कही और तर्क दिया कि भौतिक रूप से सोना जमा रखने से आर्थिक वृद्धि में उसकी भूमिका सीमित रह जाती है।

संसद की वित्त पर स्थायी समिति के सदस्य चौधरी ने कहा कि सोने के अधिक वित्तीयकरण से भारत की सर्राफा आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और चालू खाते के घाटे (कैड) पर दबाव घट सकता है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में यहां उन्होंने कहा कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पहले ही देश के कुल माल निर्यात में करीब 15 प्रतिशत योगदान देता है और करीब 50 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के मुख्य कारोबार विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने कहा कि भारत के घरों तथा मंदिरों में मिलाकर कुल 50,000 टन सोना है जिसकी कीमत करीब 10,000 अरब डॉलर आंकी जाती है और इसका बड़ा हिस्सा औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर है। उन्होंने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) के माध्यम से सोने के वित्तीयकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा, ''हमारे पास मंच है, क्षमता है एवं प्रौद्योगिकी भी है।''

2025 में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय से जुड़ी उपद्रव की 122 घटनाएं हुईं : ओडिशा सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में 2025 के दौरान हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों से जुड़ी उपद्रव की कुल 122 घटनाएं दर्ज की गईं। यह जानकारी राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश किए गए एक श्वेतपत्र से मिली। गृह विभाग ने बताया कि इस अवधि के दौरान हिंदू-मुस्लिम से जुड़ी उपद्रव की 106 और हिंदू-ईसाई से जुड़ी 16 घटनाएं हुईं, जिनमें 165 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, दस्तावेज से पता चला कि 2025 में ओडिशा के विभिन्न पुलिस थानों में दंगों को लेकर 1,095 मामले दर्ज किए गए थे।

पुलिस ने 498 दंगा मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया है, जबकि 548 अन्य ऐसे मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया जाना बाकी है, जिनकी जांच जारी है। इसमें कहा गया है, ''पिछले दशहरे के दौरान कटक शहर में भड़के सांप्रदायिक तनाव को समन्वित खुफिया जानकारी और पुलिस तैनाती के जरिए सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया गया।'' श्वेतपत्र के अनुसार, पिछले वर्ष पुरी में रथयात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। इसमें कहा गया है कि ओडिशा में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सरकार ने एक ''राज्य स्तरीय सांप्रदायिक समन्वय समिति'' का गठन किया है।

रांची में डार्क वेब के जरिये खरीदे गए एलएसडी पैच जब्त किए गए

रांची/भाषा। झारखंड के रांची में डार्क वेब का उपयोग करके डाक के माध्यम से नीदरलैंड से कथित तौर पर आयात किए गए एलएसडी के पचास पैच जब्त किए गए हैं। यह इसी तरह की दूसरी बरामदगी है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि फरवरी में पहले गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों-अभिषेक कुमार (20) और अविनाश कुमार (21) से हिरासत में पूछताछ के दौरान प्राप्त नए सुरागों के बाद हेहल डाकघर में खेप को जब्त कर लिया गया। कोतवाली पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) प्रकाश सोय ने बताया कि दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि एलएसडी युक्त एक अन्य पार्सल मंगलवार को हेहल डाकघर में पहुंचाया जाना था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया। पहले के एक मामले में पुलिस ने 25 फरवरी को दो लोगों को लगभग आठ लाख रुपए मूल्य के 1.74 ग्राम एलएसडी के साथ गिरफ्तार किया था, जो रांची में इस तरह की पहली बरामदगी थी। पुलिस के अनुसार, अवैध बाजार में प्रत्येक एलएसडी पैच की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए के बीच है।

मुझे पाकिस्तान से जोड़ना हिमंत के दिमाग की कोरी कल्पना है : गौरव गोगोई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोरहाट/भाषा। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने उनके एवं उनकी पत्नी के ''पाकिस्तान के साथ संबंध होने'' के आरोपों को बुधवार को खारिज करते हुए इन्हें मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के ''दिमाग की उपज'' करार दिया।

गोगोई ने साथ ही कहा कि ऐसे दावे मुख्यमंत्री की ''कमजोरी'' को उजागर करते हैं और यह भी दिखाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामले में वह किस हद तक जा सकते हैं। जोरहाट से सांसद ने 'पीटीआई-भाषा' से साक्षात्कार में कहा कि शर्मा द्वारा किए जा रहे हमलों और कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों में स्पष्ट अंतर है। गोगोई ने कहा, ''शर्मा जो कह रहे हैं और मैं उनके खिलाफ जो कह रहा हूं, उसमें फर्क है – उनके बेतुके आरोप केवल उनके दिमाग की उपज हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बेहद गंभीर मुद्दे से संबंधित हैं।'' उन्होंने दावा किया, ''हम उनके (शर्मा के) परिवार, उनकी संपत्ति, भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र द्वारा उनकी पत्नी की कंपनी को दिए जा रहे लाभ के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, वह सबके सामने है।'' उन्होंने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं, इस बारे में कई खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं, लोग इन आरोपों के संबंध में अदालतों में मुकदमे लड़ रहे हैं तथा सार्वजनिक रूप से एवं मीडिया में प्रकाशित साक्ष्यों की एक पूरी सूची मौजूद है। गोगोई ने कहा कि शर्मा द्वारा लगाए जा रहे आरोप ''कोरी कल्पना मात्र'' हैं। उन्होंने कहा, ''राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और इस गंभीर मामले पर ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए।''

शर्मा, गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ क्लेयर गोगोई पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाते रहे हैं और उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

झारखंड के हजारीबाग में लड़की का अपहरण कर हत्या

हजारीबाग (झारखंड)/भाषा। झारखंड के हजारीबाग जिले में बुधवार को 12 वर्षीय एक लड़की का अपहरण कर पत्थरों से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना बिष्णुगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में हुई, जहां लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि बलात्कार के बाद हत्या की गई। इसने बताया कि बुधवार सुबह ग्रामीणों ने स्कूल के पास लड़की का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि लड़की मंगलवार शाम से लापता थी, जब उसे आखिरी बार राम नवमी से पहले निकलने वाले 'मंगला जुलूस' में भाग लेते हुए देखा गया था। बिष्णुगढ़ थाना प्रभारी स्वपन कुमार ने कहा, ''प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लड़की का अपहरण किया गया और फिर पत्थरों से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और सबूत एकत्र किए।'' मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिष्णुगढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई।

ओडिशा: पांच माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया

भुवनेश्वर/फूलबनी/भाषा। ओडिशा में वांछित माओवादी सुकरू उर्फ कोसा सोड़ी सहित पांच नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ माओवाद अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि माओवादियों के खिलाफ तीन दशकों से जारी संघर्ष में 239 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल विरोधी अभियान) संजीव पांडा ने कंधमाल जिले के मुख्यालय फूलबानी स्थित पुलिस रिजर्व ग्राउंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)-माओवादी की राज्य समिति के सदस्य सुकरू (49) सहित पांच माओवादियों का आत्मसमर्पण स्वीकार करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने बताया, राज्य ने नक्सलियों के खिलाफ तीन दशकों से जारी संघर्ष में 239 सुरक्षाकर्मी खो दिए। हम शहीदों को अपनी सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

वनडे विश्व कप खिताब ने हमें दुनिया में कहीं भी जीतने का आत्मविश्वास दिया : हरमनप्रीत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को कहा कि पिछले साल घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप जीतने से टीम को दुनिया में कहीं भी और खिताब जीतने के लिए बहुत जरूरी आत्मविश्वास मिला। भारतीय महिला टीम ने पिछले साल नवंबर में नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता था। हरमनप्रीत को उम्मीद है कि 12 जून से पांच जुलाई तक ब्रिटेन में होने वाले महिला टी20 विश्व कप में भी टीम यह कारनामा दोहराने में सफल रहेगी।

द्वारका के ओमेक्स स्टेडियम में उनके सम्मान में बने स्टैंड के नामकरण समारोह के दौरान हरमनप्रीत ने कहा, ''मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ खास करना होता है। आपको कोई खिताब जीतना होता है, तभी आपको पहचान मिलती है। ऐसा न होने पर मानो लगता है कि सारी मेहनत बेकार चली गई।'' उन्होंने कहा, ''हमारी टीम ही नहीं हमसे पहले की सभी महिला क्रिकेटरों ने कड़ी मेहनत की। उन्हें तो अक्सर अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने पड़े थे। इसलिए खिताब जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। खिताब हासिल करने के बाद भारतीय प्रशंसकों, मीडिया और बाकी सभी से जो प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, वह हमारे लिए बहुत मायने रखती है।'' इस साल के टी20 विश्व कप में वनडे विश्व कप का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद के बारे में हरमनप्रीत ने कहा, ''हम टी20 विश्व कप जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। वनडे विश्व कप ने हमें जरूरी आत्मविश्वास दिया है और अब हमें विश्वास है कि हम दुनिया में कहीं भी विश्व कप जीत सकते हैं।'' भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां उसने कई प्रारूपों की शृंखला खेली, जिसमें तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच, इतने ही वनडे मैच और एक गुलाबी गेंद का टेस्ट मैच शामिल था। भारत यह शृंखला अंकों के आधार पर 4-12 से हार गया लेकिन हरमनप्रीत ने कहा कि इससे उनकी टीम को काफी कुछ सीखने को मिला।

तृणमूल ने मुस्लिम वोट तो हासिल कर लिए लेकिन समुदाय के लिए कुछ नहीं किया : ओवैसी

कोलकाता/भाषा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम वोट तो हासिल कर लिए लेकिन ''समुदाय के लिए कुछ नहीं किया।'' ओवैसी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को उभरने में मदद की।

ओवैसी ने कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और उनकी पार्टी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के साथ हाथ मिलाया है ताकि जनता को वह विकल्प प्रदान किया जा सके जिसकी उन्हें तलाश है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा, ''लगभग पांच लाख ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए। इनमें से कई मुस्लिम परिवारों से थे। क्या यह कोई मुद्दा नहीं है? उन्होंने कहा, ''यहां की आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है। सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है? केवल सात प्रतिशत। कितने मुस्लिम बच्चे स्कूल से बाहर हैं? कितने मुस्लिम लड़के-लड़कियां स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं?'' ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये प्रयास दिखावा ही रहे और राज्य में समुदाय के लिए वास्तविक विकास में तब्दील नहीं हुए। उन्होंने पूछा, ''ईद के दिन नमाज अदा करने से क्या मेरा पेट भरता है? क्या इससे मेरे घर में रोशनी होती है? क्या इससे मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है?'' हैदराबाद से सांसद ने दावा किया कि बनर्जी की राजनीति ने अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में भाजपा को अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की है उन्होंने कहा, ''बंगाल में भाजपा के तीन विधायक कब जीते थे? 2016 में ना? अब उनके पास 77 विधायक हैं। क्या मैंने उन्हें जिताया? क्या मैं इतना ताकतवर हूं कि मैंने भाजपा को फलने फूलने दिया? भाजपा का विकास आपकी आंखों के सामने हो रहा है।''

सुविचार

सम्मान माँगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आप दूसरों को जो देंगे, वही कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

साइबर ठग उठा रहे अफवाहों का फायदा

एलपीजी की किल्लत संबंधी अफवाहों का फायदा जमाखोरों के साथ ही साइबर ठग उठा रहे हैं। ये लोगों को लूटने के लिए नए-नए तरीके ढूंढ़ रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। जनता को भी जागरूक होकर इनके झांसे से दूर रहना चाहिए। इस समय कई लोग घबराहट में सिलेंडर खरीद रहे हैं। वे समाचारों पर विश्वास करने के बजाय अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वे इस मानसिक दबाव में हैं कि 'किसी तरह सिलेंडर मिल जाए, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है।' साइबर ठग इस मानसिकता का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट पर ऐसा जाल बिछा रखा है, जिससे बचने के लिए लोगों के पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में कई लोगों ने गैस बुकिंग के लिए ऑनलाइन सर्च किया तो उनके सामने जो वेबसाइट खुली, वह बिल्कुल असली लगती थी। उन्होंने 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का पेमेंट कर दिया, लेकिन किसी को सिलेंडर नहीं मिला। बाद में पता चला कि वह वेबसाइट फर्जी थी। यह तो एक घटना है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों के मोबाइल फोन पर एक लिंक भेजा गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि इस पर जानकारी देंगे तो तुरंत सिलेंडर मिल जाएगा। जिन लोगों ने लिंक पर क्लिक कर जानकारी दी, उनके पास ओटीपी आया और बैंक खातों से रुपए कट गए। बाद में पता चला कि यह साइबर ठगों की एक चाल थी। इसी तरह, दिल्ली में एक व्यक्ति से फोन पर कहा गया, 'आपको सिलेंडर चाहिए तो केवाईसी अपडेट करानी होगी।' इसके बाद उसे एक एपीके फाइल भेजी गई। व्यक्ति ने जैसे ही एपीके फाइल डाउनलोड की, उसका मोबाइल फोन हैक हो गया। साइबर ठगों ने उसके बैंक खाते से रुपए ट्रांसफर कर लिए।

कोलकाता में एक महिला के पास वीडियो कॉल आया। एक व्यक्ति ने खुद को एलपीजी एजेंसी का कर्मचारी बताया और 'वेरिफिकेशन' कराने का आग्रह किया। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की मांग की। महिला को मालूम था कि साइबर ठग ऐसी गतिविधियां करते हैं। उसने कॉल को काट दिया। अगर वह दस्तावेज सौंप देती तो ठगी की शिकार हो जाती। कुछ लोग सिलेंडर लेने के लिए बहुत हड़बड़ी में हैं। उनके सामने जो लिंक आता है, उस पर क्लिक कर देते हैं; जो क्यूआर कोड मिल जाता है, उसे स्कैन कर देते हैं। चंडीगढ़ में एक व्यक्ति ने बुकिंग कन्फर्म करने के लिए एक क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट कर दिया। उसके खाते से रुपए चले गए, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे, उसने जल्दबाजी में ठगों को पेमेंट कर दिया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक और समस्या आ रही है। कई लोगों ने एलपीजी कस्टमर केयर नंबर सर्च किए तो साइबर ठगों के नंबर मिले। ठगों ने लोगों से ओटीपी, एटीएम एवं यूपीआई संबंधी विवरण मांगा। इस तरह कस्टमर केयर नंबर सर्च करना खतरनाक हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर ही संपर्क करना चाहिए। तेलंगाना में तो साइबर ठगों ने वॉट्सऐप पर फर्जी एजेंसी ही बना दी। उन्होंने सस्ते गैस सिलेंडर और तुरंत डिलीवरी का ऑफर भी दिया। जिन लोगों ने उन्हें रुपए भेजे, उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। उन्हें कोई सिलेंडर नहीं दिया। इस तरह ठगों ने नए-नए शिकार ढूंढ़े। नोएडा में एक उपभोक्ता को यह कहकर डराया गया कि 'आपका गैस कनेक्शन बंद होने वाला है, तुरंत वेरिफिकेशन कराएं।' उपभोक्ता ने 'वेरिफिकेशन' करा दिया और साइबर ठगों ने उसके खाते में सेंध लगा दी। इन घटनाओं में एक पैटर्न दिखता है- जो लोग डरकर, जल्दबाजी में, लालच में आकर गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, वे साइबर ठगों के आसान शिकार होते हैं। जो लोग देश-दुनिया की घटनाओं से बिल्कुल अनजान हैं, वे भी लपेटे में आ रहे हैं। इसलिए सावधान रहें, जागरूक रहें। घबराहट में खरीदारी न करें। किसी के बहकावे में न आएं। अफवाहों पर विश्वास न करें। जरूरत होने पर सही तरीके से ही गैस सिलेंडर लें।

ट्वीटर टॉक

राज्यसभा सांसद एवं प्रख्यात लेखिका श्रीमती सुधा मूर्ति जी द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भगवान बुद्ध के पवित्र पीपरहवा अवशेषों की घर वापसी और लाइट एंड लोटस एक्जीबिशन पर व्यक्त किए गए विचारों का सम्मान और स्वागत है।

-गजेन्द्रसिंह शेखावत

महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम की धरा जनपद बहराइच में विकट परिस्थितियों में रह रहे 118 लाभार्थियों को पुनर्वास धनराशि एवं कृषि भूमि सहित अन्य परिसंपत्तियों के समतुल्य छ21.55 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया गया।

-योगी आदित्यनाथ

माँ दुर्गा के नौ रूप केवल आस्था नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। इसी प्रेरणा को संकल्प बनाकर राजस्थान सरकार नारी सशक्तीकरण का नया स्वर्णिम अध्याय रच रही है, जहां हर नारी सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ रही है।

-भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

कर्म और आयु

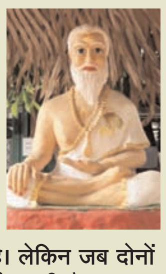

भगवान पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों के साथ गमन कर रहे थे, तभी उनके शिष्य अग्निवेश ने उनसे पूछा कि सभी प्राणियों की आयु के निर्धारण का क्या आधार है? इसके उत्तर में भगवान आत्रेय ने कहा, 'इस संसार में प्राणियों की आयु उनके कर्मों और युक्तियों पर निर्भर करती है। आयु की दीर्घता या अल्पता, सुख या दुःख, दैव (भाग्य) और पुरुषकार (स्वयं के कर्म) की शक्ति और अनुकूलता पर निर्भर करती है। जब दैव और पुरुषकार दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं, तब आयु दीर्घ, सुखमय और नियत होती है। लेकिन जब दोनों ही कमजोर होते हैं, तो आयु अल्प, दुःखमय और अनियत हो जाती है। बलवान पुरुषकार, दुर्बल दैव को पराजित कर सकता है, जबकि बलवान दैव, दुर्बल पुरुषकार को पराजित कर सकता है। इस प्रकार, कुछ लोग मानते हैं कि आयु का निर्धारण निश्चित और नियत होता है, क्योंकि दैव और पुरुषकार दोनों ही आयु पर प्रभाव डालते हैं।'

सामयिक

धर्म, जाति और धर्मांतरण : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

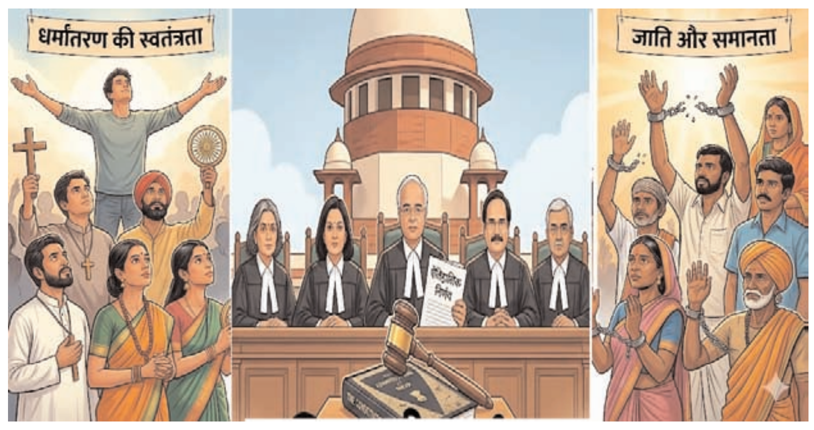

आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य भी यही था कि जो लोग सामाजिक रूप से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में अवसर मिल सके। लेकिन यदि धर्म परिवर्तन के बाद भी लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, तो इससे आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा और वास्तविक जरूरतमंद लोगों के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे समाज में असंतोष और असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

धर्म, जाति और धर्मांतरण का प्रश्न भारत के सामाजिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील और जटिल विषय है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्णय कि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वह अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा और उससे जुड़े लाभों का अधिकारी नहीं रहेगा, केवल एक सामान्य कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय की अवधारणा और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दिया गया एक दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय को भारतीय न्याय व्यवस्था की परिपक्वता, संतुलन और दूरदर्शिता का प्रतीक कहा जा सकता है।

भारत में अनुसूचित जाति की व्यवस्था का निर्माण किसी धर्म विशेष को लाभ देने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उन सामाजिक वर्गों को संरक्षण और अवसर देने के लिए किया गया था, जो सदियों से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते रहे थे। संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि समाज में जो ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक असमानता रही है, उसे दूर किए बिना वास्तविक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। इसी कारण आरक्षण और विशेष कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था मूलतः सामाजिक भेदभाव पर आधारित थी, आर्थिक आधार पर नहीं। इसलिए अनुसूचित जाति का प्रश्न धर्म से अधिक सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ था।

जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ऐसे धर्म को स्वीकार करता है, जहां जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाती, तो फिर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या उसे उसी आधार पर अनुसूचित जाति के लाभ मिलते रहने चाहिए। इसी प्रश्न को लेकर वर्षों से देश में बहस चलती रही है। कई मामलों में यह देखा गया कि व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वह दूसरे धर्म की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भी हो गया, लेकिन वह अनुसूचित जाति के आरक्षण, छात्रवृत्ति, नौकरी में आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट जैसे कानूनों का लाभ लेना चाहता था। इससे एक प्रकार की कानूनी और सामाजिक विसंगति उत्पन्न हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी विसंगति को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और यह स्पष्ट करता है कि संविधान द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग उसी सामाजिक संदर्भ में किया जा सकता है, जिसके लिए वे बनाई गई थीं।

धर्मांतरण का प्रश्न भारत में केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं रहा है, बल्कि कई बार यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनसंख्या संतुलन से भी जुड़ जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर गरीब, वंचित और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों में धर्मांतरण की घटनाएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं। कई बार धर्मांतरण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सहायता के माध्यम से हुआ, तो कई बार लालच, प्रलोभन, दबाव या सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी धर्म परिवर्तन के आरोप लगे। इसी कारण कई राज्यों ने धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए, ताकि बल, प्रलोभन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोका जा सके, लेकिन इन कानूनों का प्रभाव उतना व्यापक नहीं हो पाया जितनी अपेक्षा थी।

जब किसी विशेष सामाजिक वर्ग का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव केवल धर्म पर ही नहीं पड़ता, बल्कि जातीय संरचना, सामाजिक संतुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ता है। धीरे-धीरे यह स्थिति सामाजिक और धार्मिक संतुलन को प्रभावित करने लगती है। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुजातीय देश में सामाजिक और धार्मिक संतुलन का बने रहना राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज लगातार जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बदलता और विभाजित होता रहेगा, तो इसका प्रभाव सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता पर पड़ना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से धर्मांतरण का प्रश्न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह सामाजिक और राष्ट्रीय संतुलन का भी प्रश्न बन जाता है।

आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य भी यही था कि जो लोग सामाजिक रूप से वंचित हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में अवसर मिल सके। लेकिन यदि धर्म परिवर्तन के बाद भी लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, तो इससे आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा और वास्तविक जरूरतमंद लोगों के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे समाज में असंतोष और असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आरक्षण व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि संविधान की सुविधाएँ अधिकार हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है। यहां अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां होते हुए भी देश एक है। लेकिन यदि धर्म, जाति और जनसंख्या संतुलन को लेकर लगातार राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग होते रहेंगे, तो इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है। धर्मांतरण यदि पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था और विचार की स्वतंत्रता के आधार पर हो तो वह व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन यदि वह लालच, भय, दबाव, सामाजिक अलगाव या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो, तो वह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय संतुलन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया बन जाता है। इसलिए इस विषय पर संतुलित, संवेदनशील और राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। यह निर्णय केवल यह नहीं कहता कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह निर्णय संविधान की मूल भावना को भी स्पष्ट करता है कि सामाजिक न्याय का आधार सामाजिक वास्तविकता है, न कि केवल कानूनी तकनीक। यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि संविधान द्वारा दी गई सुविधाओं का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है, न कि कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग होने देना। आज भारत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां कानून, संविधान और न्याय व्यवस्था केवल तकनीकी व्याख्याओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सामाजिक वास्तविकता, राष्ट्रीय हित और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर निर्णय दिए जा रहे हैं। इस दृष्टि से यह निर्णय नए भारत की कानूनी सोच और संवैधानिक दृष्टि का प्रतीक भी कहा जा सकता है। यह निर्णय यह संदेश देता है कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता दोनों साथ-साथ चल सकते हैं और संविधान दोनों की रक्षा करने में सक्षम है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि धर्म, जाति, आरक्षण और धर्मांतरण का प्रश्न भारत में लंबे समय से विवाद और बहस का विषय रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस जटिल विषय को स्पष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल आरक्षण व्यवस्था अधिक स्पष्ट और न्यायसंगत बनेगी, बल्कि धर्मांतरण और कानूनी लाभ के बीच जो विसंगतियाँ थीं, वे भी काफी हद तक समाप्त होंगी। यह निर्णय सामाजिक संतुलन, कानूनी स्पष्टता और राष्ट्रीय एकता- तीनों को मजबूत करने वाला निर्णय है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि यह निर्णय केवल एक न्यायालय का फैसला नहीं, बल्कि नए भारत, सशक्त भारत और संगठित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए।

नजरिया

अशोक खरात मामले का सामाजिक विश्लेषण

महेन्द्र तिवारी

इस पूरे कांड का एक और संवेदनशील पहलू पितृत्व और डीएनए टेस्ट से जुड़ा है। खरात ने कई परिवारों को 'संतान प्राप्ति' का झूठा वादा दिया था, जिससे कई बच्चों के जन्म हुए। अब सवाल यह है कि इन बच्चों का वास्तविक पिता कौन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के तहत विवाहकालीन पैदा हुआ बच्चा पति का माना जाता है, जब तक कि गैर-पहुंच साबित न हो।

महाराष्ट्र के नासिक में खुद को त्रिकालज्ञानी और अवतारी पुरुष बताने वाले कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन' की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। यह केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि यह अंधविश्वास, सत्ता के दुरुपयोग और महिला शोषण के एक ऐसे गठजोड़ का पर्दाफाश था जिसने समाज की रीढ़ को हिला कर रख दिया। रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अधिकारी से लेकर एक प्रभावशाली ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु बनने तक का सफर तय करने वाले खरात ने अपने इस रूपांतरण का इस्तेमाल महिलाओं के यौन शोषण के लिए एक हथियार की तरह किया। नाशिक क्राइम ब्रांच ने 18 मार्च 2026 को सिन्नर तालुके के मिरगांव स्थित उसके फार्महाउस से उसे गिरफ्तार किया, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे की कहानी कई साल पुरानी थी। एक पीड़िता ने 2022 से 2025 तक के दौरान हुए उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की नींद खुली और एक बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि कैसे आध्यात्मिकता के नाम पर अंधविश्वास का व्यापार किया जाता है और कैसे कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, इसका शिकार बनती हैं।

खरात का तरीका बेहद सुनियोजित और खतरनाक था। उसने अपने आप को भगवान का अवतार और न्यूमेरोलॉजिस्ट के रूप में स्थापित किया था। श्री ईशानेश्वर महादेव ट्रस्ट का चेयरमैन बनकर उसने न केवल आम लोगों बल्कि सत्ता के गलियारों में भी अपनी पैठ बनाई थी। वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ट्रस्ट का दौरा करना और गौशाला के लिए दान देना खरात के प्रभाव का जीवित उदाहरण था।

हाई-प्रोफाइल नेता और व्यापारी हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंचते थे, जो उसके कद का अंदाजा लगाता है। लेकिन इस आध्यात्मिक चमक के पीछे एक काला सच छिपा था। खरात महिलाओं को 'योनि पूजा', 'संतान प्राप्ति' और 'पति की रक्षा' जैसे झूठे अनुष्ठानों के नाम पर अपने जाल में फंसाता था। इसका सबसे खतरनाक हथियार था 'ओश्नो जल'। यह कोई पवित्र जल नहीं बल्कि कफ सिरप, पानी और कुटी हुई वियाग्रा का मिश्रण था, जिसे पीने से महिलाओं में उत्तेजना और लत लग जाती थी। सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने जब इसका राजफाश किया, तब तक खरात अपना साम्राज्य खड़ा कर चुका था। पुलिस की जांच में पाया गया कि इस नशीले पेय का इस्तेमाल महिलाओं को बेहोश या उत्तेजित करके उनके साथ शोषण करने के लिए किया जाता था, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जो सबूत बरामद किए, वे चौंकाने वाले थे। मिरगांव फार्महाउस की तलाशी में 58 से लेकर 100 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप पेन ड्राइव में मिलीं, जिनका इस्तेमाल पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। हिडन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए, जो इस बात का सबूत थे कि यह एक संगठित अपराध नेटवर्क था। इसके अलावा, पुलिस को वहां से पिस्तौल और कारतूस भी मिले, जो खरात के आपराधिक मनोबल को दर्शाते हैं। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल मचा दिया। महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर, जो एनसीपी से संबद्ध हैं, इस विवाद में घिर गईं। सामने आए एक वीडियो में वे खरात के पैर धोती हुई दिखीं, जिसे परिवारिक श्रद्धा बताया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे संरक्षण का सबूत माना। चाकणकर ने खरात के अपराधों से अपनी अनभिज्ञता जताई और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर 19-20 मार्च 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर यह इस्तीफा स्वीकार किया गया, लेकिन विपक्ष, विशेषकर शिवसेना (यूबीटी) और सुषमा अंधारे ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने खरात को संरक्षण देने, पीड़िताओं की दलाली करने और तंत्र-मंत्र के व्यापार में शामिल होने के आरोप लगाए तथा नार्को टेस्ट की मांग की। यह राजनीतिक विवाद इस बात का संकेत है कि कैसे ऐसे गॉडमैन राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक या प्रभाव का साधन बन जाते हैं और जब पर्दा उठता है तो बड़े नेताओं की कुर्सी भी डगमगा जाती है।

इस पूरे कांड का एक और संवेदनशील पहलू पितृत्व और डीएनए टेस्ट से जुड़ा है। खरात ने कई परिवारों को 'संतान प्राप्ति' का झूठा वादा दिया था, जिससे कई बच्चों के जन्म हुए। अब सवाल यह है कि इन बच्चों का वास्तविक पिता कौन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के तहत विवाहकालीन पैदा हुआ बच्चा पति का माना जाता है, जब तक कि गैर-पहुंच साबित न हो। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ मामले में स्पष्ट किया है कि डीएनए टेस्ट रूटीन नहीं हो सकता। इसके लिए मजबूत प्राइमा फेसी सबूत जैसे धोखा या शोषण के सबूत होने चाहिए और कोर्ट के आदेश के बिना पति द्वारा टेस्ट कराना गोपनीयता के उल्लंघन के समान हो सकता है। इससे कानूनी पेचदांनियां खड़ी होती हैं, क्योंकि एक तरफ न्याय की मांग है तो दूसरी तरफ बच्चे की पहचान और मानसिक स्थिरता का सवाल। पैटरनिटी फ्रॉड से बच्चों और माताओं में डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो सकता है, इसलिए कोर्ट को काउंसलिंग को अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

सामाजिक स्तर पर देखें तो यह मामला महाराष्ट्र में अंधविश्वास की जड़ों को उजागर करता है। खरात जैसे गॉडमैन पैसे और पावर के बल पर फलते-फूलते हैं। 'ओश्नो जल' जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल केवल शारीरिक उत्तेजना के लिए नहीं, बल्कि मानसिक अधीनता के लिए किया जाता था। महिलाओं को पति की मृत्यु का भय दिखाकर या हिप्नोसिस के जरिए शोषित किया गया, जिससे उन्हें पीटीएसडी जैसी मानसिक चोटें लगीं। अंजली दमानिया जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह राज खुला, लेकिन यह सिस्टम की कमजोरी भी दिखाता है कि इतने बड़े पैमाने पर अपराध होते रहे और पुलिस या प्रशासन की आंखें क्यों खुलीं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सभी दोषियों को सजा का वादा किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल खरात को सजा मिलने से काम चल जाएगा या इसके पीछे के गिरोह और संरक्षणकर्ताओं तक भी जांच पहुंचेगी।

अंततः, यह स्कैंडल महाराष्ट्र के लिए एक कलंक बनकर उभरा है। बाबा गिरफ्तार हुआ, चेयरपर्सन ने इस्तीफा दिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। सैकड़ों पीड़िताएं अभी भी डर के मारे चुप हैं। एसआईटी को सख्ती बरतनी होगी ताकि न्याय मिल सके।

सरकार को पीड़िताओं के लिए काउंसलिंग सेंटर और कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। समाज को भी अंधविश्वास छोड़कर विज्ञान और तर्क को अपनाना होगा। डीएनए और कानून की जटिलताओं के बीच संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है ताकि पीड़ितों पर दोबारा अत्याचार न हो। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन इसके बिना न्याय असंभव है। यदि समाज को बचाना है, तो ऐसे संगठित अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आध्यात्मिकता के नाम पर किसी का शोषण न हो। खरात का मामला एक चेतावनी है कि सत्ता और अंधविश्वास का गठजोड़ कितना विनाशकारी हो सकता है, और इसे तोड़ने के लिए कानून, समाज और प्रशासन को एकजुट होना होगा।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ट्रेन के पटरी से उतरने से 25 घायल

लाहौर/भाषा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ट्रेन के सात डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 25 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंगलवार देर रात लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर लोधरान में हुई घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने प्रभावित पटरी पर यातायात निलंबित कर दिया।

रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा कि लोधरान में तेजगाम एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के पीछे मानवीय त्रुटि और कुछ यांत्रिक खराबी ही सबसे संभावित कारण हैं।

लोधरान के उपायुक्त अब्दुल हाफ़िज के अनुसार, कराची जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस मंगलवार शाम को लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। उन्होंने बताया, ट्रेन बहावलपुर-लोधरान खंड पर आदम वाहन रेलवे स्टेशन के पास रात 9:30 बजे पटरी से उतर गई।

उपायुक्त ने बताया, सात बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें कुछ यात्री फंस गए। लगभग 25 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। हालांकि, किसी की जान नहीं गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब आपातकालीन विभाग के बचाव दल 1122 ने फंसे हुए यात्रियों को बचाया और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया।

रेलवे अधिकारी ने बताया कि डिब्बों के बीच लगे कपलर के टूटने से ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। उन्होंने बताया कि ट्रेन के दो हिस्सों में बंटने के कारण इंजन से जुड़े सात डिब्बे पटरी से उतर गए।

अधिकारी ने बताया कि प्रभावित पटरी पर रेल यातायात निलंबित कर दिया गया है।

प्रचार

चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके (-ख-उच्चघ) महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (जो दिखाई नहीं दे रहे हैं) के चुनाव अभियान के दौरान कलाकार प्रस्तुति देते हुए।

भारत में प्रत्येक तीन में से एक पीसी उपयोगकर्ता ऑफलाइन साइबर हमलों का शिकार : रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। इंटरनेट से कटे होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपका कंप्यूटर सुरक्षित है; भारत में वर्ष 2025 के दौरान प्रत्येक तीन में से एक निजी कंप्यूटर (पीसी) उपयोगकर्ता स्थानीय स्तर पर होने वाले 'ऑफलाइन' साइबर हमलों का निशाना बना। साइबर सुरक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कैस्परस्काई ने मंगलवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।कंपनी ने बताया कि उसने जनवरी से दिसंबर, 2025 के बीच भारत में 6.46 करोड़ से अधिक स्थानीय साइबर घटनाओं का पता लगाया और उन्हें रोका।

ये हमले मुख्य रूप से यूएसबी और पेनड्राइव जैसे बाहरी उपकरणों के जरिये किए गए। इन स्थानीय साइबर खतरों के कारण भारत दुनिया के शीर्ष 80 सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल हो गया है।

कैस्परस्काई सिक्योरिटी नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार, देश में 29.8 प्रतिशत उपयोगकर्ता इन ऑफलाइन खतरों की चपेट में आए। इनमें 'वर्म्स' या खुद को फैलाने वाले घातक प्रोग्राम और 'फाइल वायरस' के जरिये होने वाले हमले सबसे अधिक रहे।एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए कैस्परस्काई के प्रबंध निदेशक एड्रियन हिया ने कहा, ''2025 में हमारे शोधकर्ताओं ने पाया कि हमलावर मैलवेयर डाउनलोड कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल ड्राइव जैसे लोकप्रिय टूल की नकल कर रहे हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं की बैंकिंग जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत ब्योरा चुराया जा सके।'' वैश्विक स्तर पर पासवर्ड चुराने वाले यानी गोपनीय जानकारी उड़ाने वाले खतरों में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, जासूसी करने वाले 'स्पाइवेयर' यानी चुपके से निगरानी रखने वाले सॉफ्टवेयर की घटनाओं में भी 51 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

मुलाकात

अभिनेता और फिल्म निर्माता संजय दत्त ने अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर आंध्र प्रदेश में फिल्म उद्योग के विकास पर चर्चा की।

सात समंदर पार 'धुरंधर' का डंका, एनबीए मैच में गूंजा फेमस टाइटल ट्रैक

मुंबई/एजेन्सी

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को ज्यादातर लोगों ने सिनेमाघरों में जाकर देख ही ली है, और जिन्होंने नहीं देखी, उन्होंने इसका फेमस टाइटल ट्रैक 'ना दिल दे परदेसी नू' तो जरूर सुना होगा। फिल्म की वैश्विक लोकप्रियता से तो ज्यादातर लोग वाकिफ थे, लेकिन अब इस गाने ने वैश्विक स्तर पर नई लोकप्रियता हासिल कर ली है। दरअसल, हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एनबीए मैच के दौरान फिल्म का टाइटल ट्रैक 'ना दिल दे परदेसी नू' बजाया गया। मैच शुरू होने से ठीक पहले मशहूर डांस ग्रुप 'भांगड़ा एम्पायर' ने इसी गाने पर शानदार परफॉर्मेंस दी। डांसर्स ने पारंपरिक पंजाबी कपड़े पहने हुए थे। वे रंग-बिरंगे कपड़ों में जोश के साथ भांगड़ा कर रहे थे। उनके मजेदार डांस और धुरंधर के धमाकेदार बीट्स से पूरा स्टेडियम गूंजा उठा। यह मैच गोल्डन स्टेट वॉरियर्स और मिलवॉकी बक्स के बीच खेला जा रहा था। 'भांगड़ा एम्पायर' का डांस वीडियो काफी वायरल हो गया। कई लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभिनेता अर्जुन रामपाल, जिन्होंने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ने भी वीडियो को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट किया।

फिल्म का टाइटल ट्रैक 'ना दिल दे परदेसी नू' 1995 के प्रसिद्ध पंजाबी लोकगीत 'जोगी' का रीमेक है। इस मूल गाने को चरणजीत आहूजा ने संगीतबद्ध किया था, जिसे मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने गाया था और बाबू सिंह मान ने लिखा था। इस नए संस्करण को शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है और हनुमानकाइंड और जैस्मीन सैंडलस ने गाया है। 2000 के शुरुआती सालों में रिलीज हुआ गाना 'जोगी' पंजाबी लोक संगीत को हिप हॉप बीट्स और ग्लोबल रिदम के साथ जोड़ता है।

उस समय यह एकदम नया और ताजा लगता था, जब फ्यूजन म्यूजिक इतना आम नहीं हुआ था। इस गाने ने उस समय सिर्फ ट्रेंड सेट नहीं किया था बल्कि, कई देशों में पहुंचकर कलाकारों को प्रेरित भी किया था। इसने दिखा दिया कि भारतीय संगीत अपनी जड़ों को बनाए रखते हुए भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो सकता है।

वेब सिरीज 'मां का सम' अगले महीने होगी रीलीज

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री मोना सिंह जल्द ही वेब सिरीज 'मां का सम' में नजर आएंगी। यह एक भावुक ड्रामा सिरीज है, जो प्यार, परिवार और एल्गोरिदम के अनोखे मिश्रण को पेश करेगी। निकोलस खरकोंगोर द्वारा निर्देशित सिरीज 3 अप्रैल को यह भारत समेत दुनिया के 240 देशों और इलाकों में रिलीज होगी। दर्शक इसे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे। इसमें मोना सिंह, अंगिरा धर, मिहिर आहूजा और रणवीर बराड़ जैसे कलाकार शामिल हैं। सीरीज की कहानी अगस्त्य नामक स्मार्ट टीनएज के लड़के ईर्द-गिर्द घूमती है। वह जीनियस होता है और पूरी दुनिया को नंबर्स, ग्राफ और एल्गोरिदम के नजरिए से देखता है। उसके लिए हर समस्या का एक लॉजिकल समाधान होता है। वहीं, अपनी मां के लिए सही जीवनसाथी ढ़ंढने की तलाश में भी रहता है। वह फैसला लेते हुए 'प्रोजेक्ट मॉम' की शुरुआत करता है। वह सोचता है कि मैथ की मदद से वह अपनी मां के लिए परफेक्ट पार्टनर चुन लेगा लेकिन जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ती है, लॉजिक और इमोशन के बीच टकराव शुरू हो जाता है। इस सफर में अचानक मुलाकातें, जिंदगी की अनिश्चितताएं और असली इमोशंस शामिल हैं। सिरीज ह्यूमर, अपनापन और मैथ के हल्के-फुल्के तड़के के साथ मां-बेटे के रिश्ते का एक नया और गहरा पहलू दिखाती है।

बबिता अशिवाल ने यूनोइया फिल्म्स के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। सीरीज को लेकर फिल्म के निर्माता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस सिरीज की जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह थी उस लड़के के रिश्तों को देखने का तरीका। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपनी टीनएज के आखिरी दिनों में है और मैथ व डेटा के जरिए प्यार और जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसी कहानी है जिससे आप तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं। इसकी कहानी हास्य से भरपूर है और इसमें छोटी-छोटी सीखें भी हैं जो हम सभी जिंदगी को समझने की कोशिश में सीखते हैं। प्राइम वीडियो हमेशा से काम करने के लिए एक बेहतरीन पार्टनर रहा है। 'मां का सम' एक ऐसी पारिवारिक सीरीज है जिसे पूरा परिवार एक साथ देख सकता है; यह युवाओं से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी का मनोरंजन करने का वादा करती है।

प्राइम वीडियो इंडिया के निर्देशक और ओरिजिनल्स हेड निखिल मधोक ने कहा, रिश्तों पर आधारित कहानियां हमेशा लोगों को छूती हैं क्योंकि वे उन भावनाओं और बंधनों को दिखाती हैं जो हर किसी को अपने जैसे लगते हैं। 'मां का सम' मां-बेटे के रिश्ते को केंद्र में रखकर उसे बहुत अनोखे अंदाज में पेश करती है। इसमें इस रिश्ते की कोमलता, नोक-झोंक और बिना कहे एक-दूसरे को समझने की भावना को बहुत ईमानदारी से दिखाया गया है। मोना और मिहिर ने अपने किरदारों में शानदार काम किया है। हम 3 अप्रैल को दुनिया भर के दर्शकों के लिए यह खास कहानी पेश करने जा रहे हैं।

आसान नहीं था टीवी से बॉलीवुड का सफर : उल्का गुप्ता

मुंबई/एजेन्सी

एक्टिंग इंडस्ट्री में हर कलाकार की जर्नी अलग होती है। कुछ लोग फिल्मों के जरिए पहला कदम रखते हैं तो कुछ टीवी से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में पहचान बनाकर दूसरे प्लेटफॉर्म में पैर जमाना आसान नहीं होता। अभिनेत्री उल्का गुप्ता के लिए भी टीवी से फिल्मों में कदम रखना चुनौती भरा अनुभव रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी और धीरे-धीरे फिल्मों में पहचान बनाने लगी। उल्का गुप्ता ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपने करियर के अब तक के सफर को याद किया। उल्का गुप्ता ने कहा, ''टीवी से फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैंने कई सालों तक छोटे पर्दे पर काम किया है और अभिनय की बारीकियां सीखी हैं, लेकिन जब फिल्मों में आने की बारी आई तो मुझे कई ऑडिशन्स से गुजरना पड़ा और खुद को साबित करना पड़ा। आज मैं जहां खड़ी हूं, वहां तक पहुंचने के पीछे कड़ी मेहनत है।'' बता दें कि उल्का गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत लोकप्रिय टीवी शो 'झांसी की रानी' से की थी। इस शो में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के किरदार 'मणिकर्णिका' की भूमिका निभाई थी। इस किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस शो को लेकर उन्होंने कहा, ''इस शो ने मेरे करियर को एक मजबूत नींव दी है और मेरी एक बेहतर कलाकार बनने में मदद की है।'' उन्होंने अपना फिल्मी सफर 'सिम्बा' से शुरू किया था, जिसमें उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह की बहन का रोल निभाया था। 'केरल स्टोरी 2' फिल्म में उन्होंने 'सुरेखा' का किरदार निभाया।इसे लेकर उन्होंने कहा, ''फिल्में समाज का आईना होती हैं। समाज में जो कुछ भी घटित होता है, वही फिल्मों के जरिए दिखाया जाता है। फिल्में समाज की सच्चाई को सामने लाती हैं और कई बार समस्या का हल भी दिखाने की कोशिश करती हैं।''

अपनी ही फिल्मों पर नहीं आती हंसी': प्रियदर्शन

मुंबई/एजेन्सी

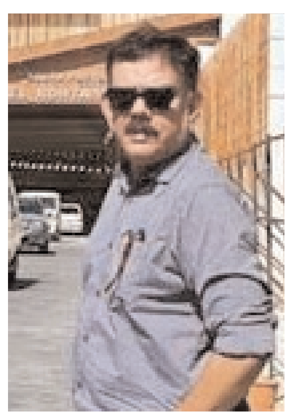

फिल्मों की दुनिया में कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस कड़ी में फिल्ममेकर प्रियदर्शन का सबसे ज्यादा बोलबाला होता है। उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी लोग देखकर हंसते हैं। लेकिन, प्रियदर्शन का खुद का नजरिया इस बारे में थोड़ा अलग है। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने बताया कि उन्हें अपनी ही फिल्मों पर हंसी नहीं आती। आईएएनएस से बात करते हुए प्रियदर्शन ने कहा, ''कॉमेडी फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है और इसमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। जब मैं अपनी ही हिट फिल्मों को दोबारा देखता हूं, तो हंसने का मन नहीं करता, जबकि वही फिल्में दर्शकों को खूब हंसाती हैं।'' प्रियदर्शन ने कहा, ''मैं हर एक सीन को कई बार देखता हूं, क्योंकि फिल्म बनाते समय एक ही सीन को बार-बार शूट और एडिट करना पड़ता है। ऐसे में जब वही सीन मैं बार-बार देख लेता हूं, तो उसमें मेरे लिए नया कुछ नहीं बचता। यही वजह है कि मुझे अपनी फिल्मों में वह मजा महसूस नहीं होता, जो पहली बार देखने वाले दर्शकों को आता है।''

उन्होंने कहा, ''जब मैं थिएटर में बैठकर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखता हूं, तो मुझे अपनी मेहनत का असली असर समझ आता है। लोग एक ही सीन को कई बार देखकर भी हंसते हैं और उसे एन्जॉय करते हैं, जो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है।''

कॉमेडी के बारे में प्रियदर्शन ने कहा, ''यह सबसे मुश्किल जॉनर है। खासकर जब इसमें डर या थ्रिल जैसे तत्व जोड़ने होते हैं, तो यह और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस तरह की फिल्में बनाते समय मुझे हर बार घबराहट होती है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है।''

प्रियदर्शन इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी और दिवंगत अनुभवी स्टार असरानी जैसे कलाकार अहम रोल में है। यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है।

महादेव की शरण में अनन्या पांडे, नागेश्वर द्वारिकाधीश मंदिर में टेका माथा

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री अनन्या पांडे अपने ड्रेसिंग सेंस और फैशन स्टाइल को लेकर दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखती हैं, जो कि हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन मंगलवार को किए गए पोस्ट में वे बेहद साधारण लुक में नजर आईं। दरअसल, अनन्या अपनी मां के साथ गुजरात स्थित प्रसिद्ध नागेश्वर द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंची थीं। इस पवित्र यात्रा की कुछ खूबसूरत झलकियां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं। पोस्ट की गई तस्वीरों में अनन्या और उनकी मां दोनों ही मंदिर के अंदर दिख रही हैं। पहली तस्वीर में अनन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव की पूजा करती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर शांति और समर्पण साफ झलक रहा है। अनन्या ने लिखा, नागेश्वर द्वारिकाधीश ओम नमः शिवाय।

अभिनेत्री सिनेमा जगत में खास पहचान रखती हैं। उनकी यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन में अनन्या की तारीफ कर रहे हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थित भगवान शिव के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक (आठवां) अत्यंत पवित्र तीर्थ है, जिसे 'नागनाथ' भी कहते हैं। यह मंदिर दारुकावन में स्थित है और मुख्य रूप से नागों के देवता के रूप में शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से पापों और सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यहां भगवान शिव की एक विशाल 25 मीटर ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, जो दूर से ही दिखाई देती है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग भूमिगत स्थापित है। रुद्र संहिता में इसे 'दारुकावने नागेशम' कहा गया है, जो एकांत और आध्यात्मिक निर्भीकता का प्रतीक है। मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण ने भी पूजा की थी। अनन्या की बात करें तो वे अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आई थीं। समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और नमः पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज की गई थी। फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया था।

रिश्ते खुली किताब जैसे हों, तभी टिकता है प्यार : सौरभ शुक्ला

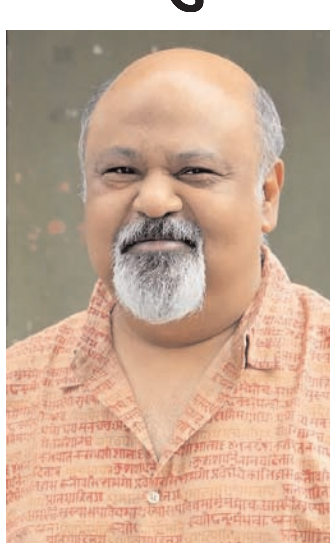

मुंबई/एजेन्सी

रिश्तों में भरोसा और समझ जरूरी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग रिश्तों को बचाए रखने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जो आगे चलकर रिश्ते के टूटने का कारण बन जाता है। ऐसे में एक सवाल को लेकर दुविधा बनी होती है कि क्या हर हाल में सच्चाई बताना जरूरी है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता और फिल्ममेकर सौरभ शुक्ला ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपनी राय रखी। सौरभ शुक्ला ने कहा, ''किसी भी रिश्ते की असली ताकत ईमानदारी होती है। हर व्यक्ति को अपने रिश्ते में एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। अपने साथी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जब कोई रिश्ते में सच छुपाता है तो उस समय भले ही बात संभाल ली जाती है, लेकिन यह रिश्ते के लिए पहले से ज्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि आपको अंधेरे में रखा गया।'' उन्होंने कहा, ''जब वह झूठ सामने आता है तो उस समय रिश्तों में दर्द इस बात का होता है कि आपको उस बारे में बताया ही नहीं गया। यही चीज एक बड़े धोखे का एहसास कराती है। ऐसे में दूसरे व्यक्ति के मन में शक पैदा हो जाता है और वह हर बात पर सवाल उठाने लगता है। इससे रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है और भरोसा टूटने लगता है।''

सौरभ शुक्ला ने कहा, ''अगर रिश्ते में खुलापन हो तो वह और मजबूत बनता है। जब दोनों लोग एक-दूसरे के सामने पूरी तरह सच्चे होते हैं तो आपसी समझ बढ़ती है। एक आदर्श रिश्ता वही होता है, जिसमें दोनों पार्टनर बिना डर के अपनी हर बात शेयर करते हैं।''उन्होंने फिल्म 'जब खुली किताब' की कहानी से इस बात को जोड़ते हुए कहा, ''फिल्म में एक कपल की जिंदगी शुरू में बिल्कुल परफेक्ट होती है, जैसे बिना किसी दरार वाली दीवार। लेकिन जैसे ही एक सच सामने आता है, उस रिश्ते में दरार आ जाती है और सब कुछ बिखरने लगता है। हालांकि, उसी दरार के जरिए सच्चाई की रोशनी भी अंदर आती है, जिससे दोनों एक-दूसरे को सही मायनों में समझ पाते हैं।'

'सौरभ ने कहा, ''जब सच सामने आता है तो छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसे में दोनों पार्टनर एक-दूसरे की अच्छाइयों और कमियों को जान लेते हैं। अगर इसके बाद भी वे साथ रहने का फैसला करते हैं तो उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है।''

महावीर जन्म कल्याणक

महामंडल द्वारा लड्डू वितरण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए बैठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां तमिलनाड जैन महामंडल द्वारा आयोजित साधारण सभा में लिए निर्णयानुसार महामंडल के सचिव मनोज जैन ने बताया कि भगवान महावीरस्वामी के जन्म कल्याणक पर 31 मार्च को करीब 10000 लड्डूओं का वितरण सदस्य मंडलों के अर्थ सहयोग से सुबह साहूकारपेट, चूले, पट्टालम, पुरुषवाक्कम व अन्य जगहों में व बिन्नी से जैन दादावाड़ी तक शोभा यात्रा में जियो और जीने दो के संदेश के साथ किया जायेगा। जिसमें महामंडल की जीवदया समिति के सदस्यों का विशेष सहयोग रहेगा।

महामंडल के अध्यक्ष ललित खांटेड ने बताया कि आप अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री व व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विभिन्न संस्थाओं, एसोसिएशन में कार्यरत कर्मचारियों व अपने ग्राहकों को 100 ग्राम का एक लड्डु इस अवसर पर देकर, इस पावन दिवस को सार्थक व पुण्यदाई बनाए। लड्डु महामंडल कार्यालय, मिंट स्ट्रीट से बुक करा सकते है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जैन दादावाड़ी में सम्पूर्ण व्यवस्था श्री तमिलनाड जैन महामंडल द्वारा की जायेगी, जिसमें महामंडल के करीब 35 मंडलों द्वारा सेवा दी जायेगी।

महामंडल के चैयरमेन कैलाश कोठारी ने बताया कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक पर 31 मार्च को तमिलनाडु में सभी क़त्ल कारखाने व शराब की दुकाने बंद रहेगी, इसे लागू करने हेतु सरकारी गजट की सूचना तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में प्रशासनिक कलेक्टरों को पत्र, गजट कॉपी व मेल द्वारा भेजी गई है।

सम्मान — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

कोयम्बटूर के तेरापंथ भवन में 25 मार्च को सूरत से आए 13 वर्षीय मुमुक्षु जहान बेताला का अभिनंदन किया गया। मुमुक्षु के रूप में तेरापंथ धर्म संघ के मुख्यमुनि श्री महावीरमुनि की निश्रा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष देवीचंद मंडोत ने स्वागत किया। स्थानीय तेरापंथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बछराज गिडिया ने मुमुक्षु जहान को पूरे जहां में नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। महिला मंडल अध्यक्ष रूपकला भंडारी ने अपने भाव व्यक्त किए। कार्यक्रम में हेमा भंसाली, सुशीला बाफना, मुमुक्षु की मामी वंदना खांटेड , मुमुक्षु की मां नताशा बेताला, शांतिलाल खांटेड , प्रेम सुराणा, निर्मल बेंगवानी, सरिता चौरडिया ने मुमुक्षु के भावी जीवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। संचालन उपाध्यक्ष बबीता गुनेचा ने किया। मुमुक्षु का माला पहनाकर शॉल ओढाकर सम्मान किया गया।

कर्नाटक बिहारी समाज के सहयोग से मुस्कान के जीवन में फिर जगी एक 'आशा की किरण'

- मृतक मजूदर बृजगोपाल की विधवा मुस्कान ने लगाई न्याय की गुहार
- डेवलपर्स की लापरवाही पर भी उठाए गए सवाल

बेंगलूरु//दक्षिण भारत। बिहार के जिला वैशाली के बिशनपुर तलौरा निवासी मजदूर बृजगोपाल बेंगलूरु शहर के निकट कोथनूर गांव के फेज-2 के क्लासिक ऑर्चर्ड्स नं. 14 पर स्थित 'एश्योरेंस डेवलपर्स' नामक भवन निर्माण कंपनी में मासिक वेतन पर एक सिविल मजूदर के रूप में कार्यरत थे। गत 27 अप्रैल 2025 को कार्यस्थल पर अपने कार्य का निर्वहन करते समय, उचित सुरक्षा व्यवस्थाओं के अभाव और नियोक्ता की लापरवाही के कारण वे एक जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो गए।

मजदूर बृजगोपाल इमारत की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थीं। चिकित्सीय उपचार के बावजूद, उसी दिन(गत वर्ष 27 अप्रैल) रात लगभग 11:30 बजे गंभीर चोट लगने व अधिक खून बह जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। बेंगलूरु में शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया। घटना के दिन 'एश्योरेंस डेवलपर्स' की ओर से 6 लाख रुपए की अनुदान राशि का पोस्टडेटेड एक चेक तथा बकाया वेतन, शव के परिवहन और अंतिम संस्कार आदि के मद में नगद राशि मृतक की पत्नी मुस्कान को दे दी गई। मुस्कान ने अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद निश्चित तिथि पर चेक को बैंक में डाला तो वह बाउंस (अनादरित) हो गया। चेक को बाउन्स हुए लगभग एक साल हो गया है । मृतक के परिजनों ने 'एश्योरेंस डेवलपर्स' से अपने स्तर पर कई बार सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं।

इस पूरे मामले की जानकारी जब कर्नाटक बिहारी समाज बेंगलूरु उत्तर के अध्यक्ष रामशंकर सिंह को मालूम हुई और उन्होंने इस मामले में अपनी ओर से गहराई से पता लगाया तो पता चला कि मृतक के परिवारजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है और दिया गया 6 लाख रुपए का चेक भी बाउंस हो गया है तो उन्हें बेहद वेदना हुई। उन्होंने बिहार मूल के मृतक मजूदर बृजगोपाल की पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली और पाया कि पति के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी मुस्कान जीवन यापन के लिए काफी कष्ट उठा रही हैं। वह चार वर्ष के एक पुत्र के साथ मुस्कान यलहंका में है। रामशंकर सिंह ने कर्नाटक बिहारी समाज के संस्थापक उदय कुमार सिंह के साथ मिलकर इस मामले की शिकायत पुट्टनहल्ली पुलिस थाने में की और पुलिस केस को फिर से खोलने की अपील की। समाज के साथ मिलकर मुस्कान ने अपनी शिकायत में पुलिस को इस केस में एश्योरेंस डेवलपर्स' के विरुद्ध एफआईआर करने की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पुन: प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। समाज के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मुस्कान ने बन्नरघट्टा रोड स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कर न्याय की अपील की है। मजदूर के हक की इस लड़ाई में संजीव कुमार सिंह, बबन सिंह, कुमोद सिंह, रमन सिंह आदि लोग प्रयास कर रहे हैं।

मायुमं बेंगलूरु ने की गौसेवा व गौपूजा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । मारवाड़ी युवा मंच(मायुमं) बेंगलूरु के सदस्यों ने रविवार को बन्नरघट्टा रोड स्थित श्याम गौशाला में गौसेवा एवं गौपूजा की। कार्यक्रम की शुरुआत गौमाता की पूजा एवं आरती से हुई।

इसके पश्चात सभी सदस्य परिवारजनों ने अपने हाथों से गायों को हरा चारा, गुड़ एवं अन्य सामग्री अर्पित की। सदस्य परिवाजजनों ने गौशाला में सहयोग राशि भी भेंट की। संयोजक अशोक अग्रवाल एवं अमित यादुका ने कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली।

इस मौके पर अध्यक्ष गोपाल कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अंकित मोदी एवं स्नेह कुमार जाजू, प्रांतीय उपाध्यक्ष जय प्रकाश अग्रवाल, सचिव सनी जैन सहित अनेक सदस्य अपने परिवार के साथ उपस्थित थे।

शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की नितांत आवश्यकता : विजय सुराणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/मुम्बई। राष्ट्रीय भैरव भक्त परिवार के कर्नाटक राज्य इकाई के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुम्बई में आयोजित 'विजयपथ कार्यक्रम' में दक्षिण नाकोड़ा सेवा संकल्प ट्रस्ट के संस्थापक चेयरमैन विजय कुमार सुराना ने कहा कि मंदिर के साथ-साथ समाजहित के लिए कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कर विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु संपूर्ण रूपरेखा तय की जाएगी। सुराणा ने उपस्थित जनों से शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाने व सहयोग देने की अपील की तथा कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की नितांत आवश्यकता है। मुंबई दौरे में विजय सुराणा के साथ ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी हुब्बल्ली के गौतम बाफणा, शिकारीपुर के जितेन्द्र संचेती, हासन के प्रवीण परमार, बेंगलूरु के मनोज बाफणा आदि उपस्थित थे। ङ्कङ्कइस मौके पर भायंदर नगर पालिका के पार्षद एवं आल इंडिया संगीत भेरु ग्रुप के संस्थापक भरत कोठारी ने कहा कि शीघ्र ही वे मुम्बई स्तर पर बातचीत कर ट्रस्ट के इस शिक्षा प्रोजेक्ट में सहयोग करेंगे तथा कर्नाटक के अरसीकेरे-टिपटूर या कडुर-बीरुर के बीच में शिक्षा के लिए विश्वस्तरीय सुविधा या रियायती शुल्क वाला छात्रावास बनाने पर विचार विर्मश किया जाएगा। अंत में ट्रस्ट के ट्रस्टियों का सम्मान किया गया।

नवपद की महिमा अपरंपार है : गणिवर्य मनीषप्रभ

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। स्थानीय जिनकुशलसूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित नवपद ओली के प्रथम दिवस पर अरिहंत पद की आराधना गणिवर्य मनीषप्रभसागर जी की निश्रा में सम्पन्न हुई। इस मौके पर गणिवर्यश्री ने कहा कि अगर अरिहंत नहीं होते तो करुणा का इतना प्रचार, धर्म का ज्ञान और शासन की स्थापना नहीं होती। जैन जगत में नवपद की महिमा अपरंपार है।

नवपद यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना। यह आराधना वर्ष में दो बार आयंबिल तप द्वारा की जाती है।

सिख समुदाय को 'आहत' करने के आरोप में 'धुरंधर' सीक्वल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुंबई में एक सिख संगठन ने फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के निर्माताओं और मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

शिकायतकर्ता 'सिख्स इन महाराष्ट्र' के अनुसार, फिल्म के एक पोस्टर में सिंह को पगड़ी, लंबी दाढ़ी और 'कड़ा' (कंगन) पहने हुए दिखाया गया है, जिन्हें सिख समुदाय के पवित्र प्रतीक माना जाता है।

आरोप में कहा गया कि अभिनेता को हाथ में सिगरेट पकड़े हुए भी दिखाया गया है और इस चित्रण से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है।

यह आरोप 17 मार्च को मुलुंड पुलिस थाने में दायर शिकायत में लगाया गया है।

संगठन ने फिल्म के निर्देशक, निर्माता और सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और जांच जारी है।

यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर कमाई का 700 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म आदित्य धर की 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जिसने विश्व स्तर पर 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी।

'धुरंधर: द रिवेंज' का निर्माण ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने किया है और यह हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है।

रिसर्च फाउंडेशन फॉर जैनोलॉजी ने समाज और विद्वानों के बीच संवाद करवाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। रिसर्च फाउंडेशन फॉर जैनोलोजी (आरएफजे) के सहयोग से मद्रास विश्वविद्यालय के जैनविद्या विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 23 मार्च, सोमवार शाम को समाज और विद्वानों के बीच संवाद का कार्यक्रम रखा गया। इसमें जैन अकादमी ऑफ स्कॉलर्स (जेएएस), अहमदाबाद का सहयोग भी रहा। अकादमिक आयोजन के साथ इस अभिनव पहल के सूत्रधार साहित्यकार डॉ. दिलीप धींग ने भारतीय विवाह परंपरा की महत्ता बताने वाली अपनी चर्चित कविता 'प्रतीक्षा' सुनाई और समय पर विवाह की महत्ता बताई। कवि डॉ. धींग ने कहा कि जैनविद्या के क्षेत्र में स्तरीय व नवीन शोधकार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। जैनोलॉजी टीम चेयरमैन कांतिलाल एच. सिंघवी ने आम आदमी तक अहिंसक मूल्यों के विस्तार पर जोर दिया। हिंदी ग्रंथ कार्यालय, मुंबई के मनीष मोदी ने पीपीटी के जरिए 'रिवाइविंग जैनिज्म' पर विचार रखे।

जेएएस के संस्थापक वैज्ञानिक प्रो. नरेन्द्र भंडारी ने विद्वान तैयार करने की तो जैन कॉन्फ्रेंस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला एस. मेहता ने स्वाध्यायी बनाने की बात कही। 'जिनवाणी' (मासिक) के संपादक डॉ. धर्मचंद जैन ने कहा कि युवा क्रियाकांड में नहीं, अध्यात्म में विश्वास करता है। उन्होंने विद्वेषजनक बातों से बचने की सलाह दी। आरएफजे के मंत्री संपतकुमार बागमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में पदस्थापित विद्वानों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जयप्रकाश ललवाणी ने मौलिक शोध करने वालों के सुरक्षित भविष्य की बात कही। संवाद में सिकुड़ता समाज, घटते संस्कार, जैन दर्शन की वैज्ञानिकता आदि को जन-जन तक कैसे पहुँचाए आदि विषयों पर खुली चर्चा हुई, जिसमें संगोष्ठी निदेशक डॉ. प्रियदर्शना जैन, आरएफजे की कार्यकारी निदेशक डॉ. संतोष सुराणा, चंद्रप्रभु जैन नया मंदिर ट्रस्ट के विमल शाह, सीए अनिल खीचा, पदमचंद गांधी, डॉ. अशोक जेतावत, संदेश जैन आदि अनेक प्रतिभागियों ने विचार रखे। डॉ. अनिलकुमार जैन ने सबके विचारों पर आधारित एक घोषणा-पत्र' बनाया और सबके समक्ष रखा। काजल जैन ने जागरण गीत सुनाया।

कार्यक्रम में आरएफजे के अध्यक्ष कैलाशमल दुगड़, उपाध्यक्ष सुगालचंद जैन, चन्द्रप्रभु जैन कॉलेज के अध्यक्ष नेमीचंद कटारिया, सचिव ललित ओ. जैन, श्वे.स्था. जैन संघ, मांबलम के अध्यक्ष डॉ. उत्तमचंद गोठी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य राजेन्द्र प्रसाद जैन, डॉ. चक्रवर्ती देवकुमार, सुरेश संचेती आदि अनेक महानुभाव उपस्थित थे। प्रारंभ में आरएफजे के महासचिव पदम टाटिया ने स्वागत भाषण दिया। अंत में प्रबोध जैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रत्न संघ, तमिलनाडु के पूर्व कार्याध्यक्ष आर.नरेन्द्र कांकरिया और डॉ. दिलीप धींग ने मंगलवार शाम को मद्रास विश्व विद्यालय में सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई से आए डॉ. शुद्धात्म प्रकाश जैन को अष्टपाहुड ग्रंथ भेंट किया।

परोपकार ही अरिहंत पद की सच्ची आराधना : आचार्य कुलबोधिसूरीशरजी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां किलपॉक श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ में विराजित आचार्यश्री कुलबोधिसूरिश्वरजी म.सा. के सान्निध्य में नवपद ओली के प्रथम दिन अरिहंत पद की आराधना श्रद्धालुओं की विशाल उपस्थिति में अत्यंत उत्साह, उमंग और भक्तिभाव के साथ सम्पन्न हुई। इस अवसर पर आचार्यश्री ने अपने चिर-परिचित प्रभावशाली अंदाज में धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनादिकाल से आत्मा इस संसार में भटकती हुई चारों गतियों का भ्रमण कर चुकी है। इस भटकाव के कारण शाश्वत स्वरूप वाली आत्मा के चारों ओर अशाश्वत पदार्थों का घेरा बन गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि शाश्वत तत्व सीमित हैं, परन्तु उनकी शक्ति अपार है, जबकि अशाश्वत पदार्थ असीमित होकर भी शक्तिहीन हैं। आचार्यश्री ने बताया कि हमें प्राप्त

शाश्वत आधारों में मंत्रों में नवकार, तीर्थों में शत्रुंजय- गिरीराज तथा पर्वों में नवपद का विशेष स्थान है। यदि इन शाश्वत तत्वों को जीवन में आत्मसात कर लिया जाए, तो अशाश्वत शक्तियां हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकतीं।

जिनशासन की महिमा का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें असंख्य योग निहित हैं, जिनमें नवपद योग सर्वश्रेष्ठ है। भवसागर की कठिन यात्रा को पार करने के लिए उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा कि नवपद का आश्रय लेने से कुछ ही भवों में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने यह भी बताया कि जिनशासन में नव' अंक का विशेष महत्व है, जो विभिन्न आध्यात्मिक आयामों में अपनी चमत्कारिक उपस्थिति दर्शाता है। अरिहंत पद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आचार्यश्री ने कहा कि यदि अरिहंत भगवान ने मोक्षमार्ग का उपदेश न दिया होता, तो सिद्ध पद की प्राप्ति भी संभव न होती। उन्होंने बताया कि अरिहंत का मूल स्वभाव करुणा और परार्थ है, जो जिनशासन का हृदय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परोपकार ही अरिहंत पद की सच्ची आराधना है और जब तक परोपकार हमारे जीवन में नहीं उतरता, तब तक अरिहंत पद की पूजा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। आचार्यश्री ने नवपद आराधना के पाँच सोपानों-प्यास, प्रयास, प्राप्ति, प्रसन्नता और प्रसाद-का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक साधक के भीतर प्यास, प्रयास नहीं होगा, तब तक आराधना के फल की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मोती पाने के लिए समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है, केवल किनारे खड़े रहने से कुछ नहीं मिलता।

नेत्र शिविर — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में 25 मार्च को अविशा स्माइल्स डेंटल क्लिनिक में 40वा निशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। यह शिविर नेमीचंदजी कमला देवी सिंघवी, कुचेरा(नागौर जिला), संगम ग्रुप, और एम एन आई हॉस्पिटल के सहयोग से हुआ। शिविर में महिपाल सिंघवी रणजीत शाह, उगमराज सुराना, डॉ.योगीता और हितेश का योगदान रहा। जिसमें 36 लोगों ने नि:शुल्क आंखों की जांच कराई , 9 लोगों को चश्मे दिए जाएंगे और 1 व्यक्ति का मोतियाबिन्द ऑपरेशन नि:शुल्क कराया जाएगा। अगला शिविर 8 अप्रैल को होगा।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.